कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा

विषय-सूची

खुदरा व्यापार में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के विरोध में 1 दिसम्बर 2011 को भाजपा समर्थित 'भारत बंद' पूरी तरह सफल रहा। देशभर के हजारों व्यापारिक संगठनों से जुड़े करोड़ों कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं।

एफडीआई का विरोध

श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री अरुण जेटली का संयुक्त वक्तव्य..... 7
श्री नितिन गडकरी द्वारा 'भारत बंद' के समर्थन में प्रेस वक्तव्य..... 8
खुदरा व्यापार में एफडीआई के खिलाफ भारत बंद..... 9

लेख

अपने जाल में फंसी सरकार
-अरुण जेटली..... 17
भारतीय राजनीति के गौरव हैं अटलजी
-प्रभात झा..... 19
पलायन से झेला बेइंतिहा दर्द
-संजय मिश्रा..... 21
कर्मयोगी कुशाभाऊ ठाकरे
-प्रभात झा..... 23

मोर्चा/प्रकोष्ठ

भाजपा राष्ट्रीय सुशासन प्रकोष्ठ की बैठक..... 25
भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा..... 27
भाजपा मानवाधिकार प्रकोष्ठ की पद यात्रा..... 30
भाजपा निवेशक प्रकोष्ठ का विरोध मार्च..... 30

अन्य

हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप सम्मिट में आडवाणीजी का भाषण..... 13

बोध कथा

'मैं ईश्वर के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं'

पुराने समय की बात है– इंग्लैण्ड के राजा कैन्यूट के दरबार में ऐसे लोगों का जमघट लगने लगा था, जो राजा की प्रशंसा के पुल बांधकर ओहदे तथा धन पाने के आकांक्षी थे। एक खुशामदी ने एक दिन कहा– 'सम्राट्! आपकी कीर्ति पूरे संसार में फैल चुकी है, आप तो धरती पर ईश्वर हैं, आपके आदेश को समुद्र भी नहीं टाल सकता।'

एक सन्त को जब इसका पता चला तो उन्होंने दर्शन करने आये राजा कैन्यूट को चेताते हुए कहा– 'इन खुशामदियों से बचकर रहो। तुम्हें ईश्वर बताकर ये तुम्हारा अहंकार बढ़ा रहे हैं। इनकी जिह्वा पर लगाम कसो।'

कैन्यूट ने अगले ही दिन आपने को ईश्वर बताने वाले दरबारी को पास बुलाया और उसे वे समुद्र तट पर घुमाने साथ ले गये। समुद्रतट पर पहुंचकर राजा बोले– 'मैं ईश्वर होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूं कि समुद्र की लहरों में कूद पड़ो। यदि तुम डूबने लगे तो मैं समुद्र को आदेश दूंगा। उसकी लहरें तुम्हें समुद्रतट पर छोड़ जाएंगी।'

राजा के शब्द सुनते ही मृत्यु के भय से वह लम्पट खुशामदी पसीने से तर–बतर हो उठा।

राजा ने कहा– 'तुम छली–चापलूसों की चाल को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम मुझे ईश्वर बताकर लाभ उठाना चाहते हो। जबकि सच यह है कि मैं तो ईश्वर के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। आज से मेरे पास आने का दुस्साहस न करना, वरना जीवन जेल में गुजारना होगा।'

सम्राट् कैन्यूट ने उसी दिन से चापलूसों से मुक्ति पा ली।

–शिवकुमार गोयल
'कल्याण' से साभार

व्यंग्य चित्र

हमें लिखें...

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
ई-मेल:
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको नियमित मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको कोई अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

सम्पादकीय

"भारत बंद" के बाद भी कांग्रेस मजबूर क्यों?

संसद पूरी तरह ठप्प। कांग्रेसनीत यूपीए सरकार नहीं चाहती है कि संसद में कालाधन, भ्रष्टाचार और महंगाई पर चर्चा हो। चर्चा से "भागना", यह यूपीए सरकार का शगल बन चुका है। 'संसद' की गरिमा को चोट पहुंचाने का यह क्रम यूपीए–II में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। भारत की संसद ने पूर्व में कभी ऐसी सरकार नहीं देखी। सरकार के बारे में लोग कह रहे हैं कि सरकार हो तब तो चले। आम नागरिकों का देश में वर्तमान यूपीए सरकार से मोह भंग हो रहा है। मजेदार मामला यह है कि जो बात आम जनता समझ रही है, उन बातों को अपने को समझदार मानने वाली केन्द्र की यूपीए सरकार समझ नहीं पा रही है।

संसद चलते में बिना विपक्ष ही नहीं अपने गठबंधन के घटकों से भी बिना किसी चर्चा खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश (एफडीआई) को लागू करने का निर्णय पूरे देश को नागवार गुजरा है। दलीलें चाहे जितनी दें पर देश को यह बात गले नहीं उतर रही कि आखिर भारत में 'वालमार्ट' क्यों? भारत का खुदरा व्यापार मात्र व्यापार नहीं बल्कि एक परम्परा है। एक विश्वास का संबंध ग्रामीण और उस खुदरा व्यापारी के साथ होता है जो वर्षों उस मोहल्ले या बाजार में काम करता है। हम सभी जानते हैं कि गांव के हाट और छोटे–छोटे बाजार आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूती के केन्द्र हैं। कांग्रेस चाहे लाख दलीलें दे पर उनकी दलीलों में राजनीति है और इस बात का साफ संकेत है कि डॉ. मनमोहन सिंह अमेरिकापरस्त मानसिकता के ज्वर से ग्रसित हैं।

कांग्रेस क्यों नहीं समझ रही कि अपने देश का वह व्यापार का परिवार जिससे लाखों लोग जुड़े हों तो क्या उस व्यापार पर विदेशी व्यापार का प्रहार होना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि हम अपनी शर्तों पर उन्हें ला रहे हैं। देश जानना चाहता है कि आखिर कांग्रेस की मजबूरी क्या है? कांग्रेस अपनी मजबूरी का खुलासा करे।

कांग्रेस इस बात को क्यों नहीं समझ रही कि उनके सहयोगी घटक दल भी उनका खुला विरोध कर रहे हैं। क्या वे सहयोगी दल भाजपा के हाथों खेल रहे हैं? ऐसा नहीं है। बल्कि सच्चाई यही है कि गरीब, जिसका सहारा रोज कमाना और रोज घर चलाना है, के साथ अन्याय हो रहा है। हम जानते हैं देश में व्यापार के केन्द्र दो नहीं हो सकते। अंततः आम आदमी पर भी इसका असर पड़ेगा। दूसरी बात हम देश में किसानों की चिंता नहीं कर रहे हैं। न ही हम अपनी उन मंडियों की चिंता कर रहे हैं, जहां किसानों की जिंदगी पलती है।

भारत का खुदरा व्यापार एक सामाजिक कड़ी और सामाजिक समन्वय का आधार है। गांव से शहर आते–आते खुदरा व्यापार में अनेक लोगों से व्यापारिक रिश्ते आते हैं। भारतीय खुदरा व्यापार समाज को हर स्तर पर प्रभावित करता है। अगर इस व्यापार में विदेशी निवेश आ गया तो वह सिर्फ मुनाफा देखेगा। साथ ही धीरे–धीरे

भारतीय जनता पार्टी, मध्यप्रदेश ने सीडी के माध्यम से पार्टीनीत मध्यप्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में जन–जागरण करने की अभिनव योजना बनाई है। प्रदेश भाजपा सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ द्वारा निर्मित इस सीडी में राज्य सरकार के 168 कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित सूचना एवं आवेदन–पत्र शामिल है।

मध्य प्रदेश भाजपा द्वारा विकास-यात्रा का आयोजन

मध्यप्रदेश भाजपा जनता की सेवा के उद्देश्य को लेकर अपने विशाल जन–जागरण अभियान के तहत 'विकास–यात्रा' का आयोजन करने जा रही है। यह यात्रा 230 विधानसभा क्षेत्रों में 394 शहरों एवं 52,117 गांवों से होकर गुजरेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य जनता से सीधे तौर पर जुड़ना है एवं उन्हें सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना है। यह यात्रा सरकार की सामूहिक पहल., समन्वय, संवाद और विश्वास की अहम कड़ी साबित होगी। साथ ही 'सुराज से अंत्योदय' के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगी।

वह देश के गांवों तक पहुंचेंगे और हम सभी जानते हैं कि जो ताना–बाना है वह भी प्रभावित होगा। आखिर हम क्यों चाहते हैं कि देश के करोड़ों हाथ बेकार हों। हम स्वदेशी व्यापार को विदेशी व्यापार के दांव पर क्यों लगाना चाहते हैं? 'वालमार्ट' की दुकानों को लाकर हम क्या महंगाई पर काबू कर लेंगे? ये दलील बहुत लचर है। जबकि जानकारों का दावा है कि इससे बेकारी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। बहरहाल, देश नहीं चाहता कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश हो तो वर्तमान कांग्रेसनीत यूपीए सरकार बलात् क्यों थोपना चाहती है इस निर्णय को। देश इस बात का उत्तर जानना चाहता है और कांग्रेस इस उत्तर से कन्नी काट रही है। ■

एफडीआई निवेश से भारत को मैन्युफैक्चरिंग तथा सेवाक्षेत्र दोनों में ही रोजगार का भारी नुकसान

भारतीय जनता पार्टी खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को शुरू करने के खिलाफ है। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पर सेवा क्षेत्र का अधिकार बना हुआ है। सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी का 58 प्रतिशत बैठता है। भारत में लघु एवं बड़े दोनों प्रमुख क्षेत्रों में रिटेल चेन का ही दबदबा है। भारत का स्व–राजगार नौकरियों के मामलें में एक मात्र सबसे बड़ा स्रोत है। भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा स्व–राजगार वाला है। यदि एफडीआई इस क्षेत्र में प्रभुत्व रूप से छा जाती है तो इसका हमारे बढ़ते हुए घरेलू खुदरा क्षेत्र पर अत्यंत बुरा असर पड़ेगा। उपभोक्ता वस्तुओं के लिए समेकित (consolidated) बाजार की अपेक्षा आंशिक (Fragmented) बाजार की आवश्यकता होती है। आंशिक बाजार से उपभोक्ताओं के पास कहीं अधिक विकल्प मौजुद रहते हैं। समेकित बाजार से उपभोक्ता बंदी बन कर रह जाता है। किसी भी एक क्षेत्र को बाजार में अधिपत्य नहीं जमाने देना चाहिए। विदेशियों को घुसने की छूट देने से इस प्रकार का समेकन पैदा हो जाएगा जिससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी और 'मैन्युफैक्चरिंग' तथा सेवा दोनों ही क्षेत्रों में नौकरियां भी समाप्त होकर रह जाएंगी।

बिचौलियों की समाप्ति के नाम पर ये नौकरियां स्वाह हो जाएंगी जिससे स्पष्ट है कि खुदरा क्षेत्र को भी नुकसान होगा। 'मैन्युफैक्चरिंग' क्षेत्र की नौकरियों में नुकसान इसलिए होगा क्योंकि संरचित अन्तर्राष्ट्रीय खुदरा बाजार की खरीदारी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी और इसके घरेलु स्रोत समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार के अनुभव प्रायः ऐसे सभी देशों में देखे गए हैं जहां खुदरा व्यापार में 'एफडीआई' की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापारी कम से कम कीमत पर

विपक्ष की नेता (लोकसभा) श्रीमती सुषमा स्वराज और विपक्ष के नेता (राज्यसभा) श्री अरुण जेटली द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य

खरीदते है और अधिक से अधिक कीमत पर बेचते हैं। वे पूर्व–दिनांकित कीमतों में चीजें खरीदने का काम करते हैं जिससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है और अन्ततः 'मोनोपोली' सिक्का जमा लेती है। इससे बड़े–बड़े राष्ट्रों की 'फूडचेन' पनपती है जिस पर विदेशी संस्थाओं का नियंत्रण रहता है। वर्तमान में जितना अधिक खुदरा स्थापनाओं का अधिकार है, वह बहुत हद तक बड़ी–बड़ी स्थापनाओं के हाथों में चला जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय खुदरा से अतिरिक्त बाजार नहीं बनते हैं, बल्कि इससे वर्तमान बाजारों का ही विस्थापन होता है।

यह तर्क देना कि भारत को खेती के क्षेत्रों में 'सप्लाई चेन' की आवश्यकता है और केवल विदेशी व्यापारी ही इसकी पूर्ति कर सकते हैं, एकदम खारिज की जानी चाहिए। भारत को उपभोक्ताओं के पास किसानों की उपज पहुंचाने के लिए 'इंफ्रास्ट्रक्चर' की आवश्यकता है। इससे अत्यंत सस्ती कीमत और कुशल ढंग से पूरा किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय खुदरा क्षेत्र का ग्रामीण तथा नगरीय दोनों में ही सड़कें बनाने या बिजली उत्पादन में कोई भूमिका नजर नहीं आती है। उनकी आवश्यकता तो भण्डारण सुविधा और शीत भण्डारण के लिए हो सकती है। इसे केन्द्र में भारत सरकार और राज्य क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या आप अपनी खाद्य आपूर्ति को विदेशियों के हाथों में केवल इसलिए सौंप देंगे क्योंकि सरकारें ऐसी शीत भण्डारण करने में असमर्थ रहे हैं?

भारत और चीन के बीच अन्तर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार की अनुमति देने की तुलना गुमराह करने वाली है। चीन का व्यापार प्रमुख रूप से 'मैन्युफैक्चरिंग' प्रणाली पर आधारित है। यह वालमार्ट और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

इस प्रकार का आपूर्तिकर्ता होने के नाते चीन अपने लिए 'मैन्युफैक्चरिंग' में विशाल स्तर पर नौकरियां पैदा करता है। स्पष्ट है कि वह चीन में उनके भण्डारों को खोलने के लिए मना नहीं कर सकता है। जबकि चीन उनका 'सप्लायर' है। इसके विपरीत भारत को 'मैन्युफैक्चरिंग' और सेवा दोनों ही क्षेत्रों में नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। ■

यूपीए सरकार ने खुदरा व्यापारियों के लिए खोला संकट द्वार

Hkkरतीय जनता पार्टी यूपीए सरकार द्वारा मल्टी ब्रांड सेक्टर में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दिए जाने को पूर्णतया राष्ट्रविरोधी मानती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी सरकार के इस कदम का संसद और संसद के बाहर जोरदार विरोध करेगी तथा यूपीए सरकार द्वारा एफडीआई को दिए गए मंजूरी के विरोध में खुदरा व्यापारियों के हित व अस्तित्व की सुरक्षा हेतु दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 को भारत के विभिन्न सामाजिक व व्यापारिक संगठनों यथा – कंफेडरेशन ऑफ ऑल इण्डियन ट्रेडर्स, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, भारतीय मजदूर संघ आदि द्वारा आहूत ''भारत बंद'' का सम्पूर्ण सहयोग व समर्थन करेगी। भारतीय जनता पार्टी खुदरा व्यापारियों को इस आकस्मिक कृत्रिम संकट से उबरने के संघर्ष में अपना योगदान प्राथमिक कर्तव्य समझती है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा मल्टी ब्रांड सेक्टर में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दिया जाना पूर्णतया राष्ट्रविरोधी है। इससे भारत के किसानों और छोटे दुकानदारों, जो इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से पहले से ही अपना अस्तित्व बचाने में संघर्षरत हैं, का समूल नाश हो जाएगा। मल्टी ब्रांड क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति सरकार का एकतरफा निर्णय है और उसने विपक्ष से बिना विचार–विमर्श किए ही यह निर्णय लिया है। गौर करने की बात है कि संसद की दो स्थायी समितियों ने

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा 'भारत बंद' के समर्थन में 26 नवम्बर, 2011 को जारी प्रेस वक्तव्य

भी इसके विरोध में अपने विचार व्यक्त किए हैं, परंतु इस विवेकहीन सरकार ने उनके विरोध को दरकिनार कर अपना एकतरफा निर्णय ले लिया तथा खुदरा व्यापारियों के लिए संकट के द्वार खोल दिए। इससे सबसे ज्यादा खतरा खुदरा व्यापारियों को ही है। पूरे विश्व से इसका उदाहरण लिया जा सकता है कि अब तक जहां जहां इसे लागू किया गया वहां आज खुदरा व्यापारी नहीं पाए जाते हैं यानि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया।

श्री गडकरी ने कहा कि भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था जिस हालत में है उसमें यह नीति उसके आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि देश में खुदरा व्यापार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले दस सालों में इनके विकास में व्यापकता आने की सुनहरी सम्भावनाएं हैं। यह बात स्वयं सरकार ने भी माना है। फिर अचानक ही इस नीति को मंजूरी देकर उनके विकास के पौधे पर तुषारापात करने की कार्यवाही खुदरा व्यापारियों की अप्रत्यक्ष हत्या के समान है। यह हमारे विकासशील अर्थव्यवस्था के विकास में भी घातक सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि पूरे भारत के जीडीपी का 58 प्रतिशत खुदरा व्यापार के क्षेत्र से ही आता है। गौर करने की बात है कि इस खुदरा व्यापार के माध्यम से स्वरोजगार द्वारा भारत में बेरोजगारी पर काबू पाना एक महत्वपूर्ण साधन है। ऐसे में इस नीति के लागू होने से आर्थिक विकास तो अवरूद्ध होगा ही समाज का बुनियादी ढांचा भी चरमरा जाएगा।

श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का यह तर्क कि रूपये की गिरती कीमत को सम्भालने हेतु विदेशों से डॉलर लाकर उसे मजबूत बनाने के लिए यह मंजूरी दी गई है। यह तर्कसंगत नहीं लगता क्योंकि वास्तव में सरकार की अपनी गलत नीतियों के कारण ही रूपये की कीमत लगातार गिरती जा रही है। इसे सम्भालने के लिए पहले से ही उचित और व्यापक कदम उठाए जाने आवश्यक थे, जो सरकार ने समय रहते नहीं किया।

श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य केन्द्र सरकार के इस फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। ■

खुदरा व्यापार में एफडीआई के खिलाफ

भारत बंद का व्यापक असर

बाजारों में पसरा सन्नाटा, नहीं खुली दुकानें

खुदरा व्यापार में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के विरोध में 1 दिसम्बर 2011 को 'भारत बंद' पूरी तरह सफल रहा। देशभर के हजारों व्यापारिक संगठनों से जुड़े करोड़ों कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं। इस बंद को भारतीय जनता पार्टी के अलावा सीपीएम, सीपीआई, जदयू, बीएसपी एवं एसपी का समर्थन प्राप्त था। पूरे देश में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। देश के कोने–कोने में एफडीआई के विरोध में रैली निकालकर पुतले जलाए गए और सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में नारे लगाए गए। भारत बंद इतना सफल रहा कि इसने केन्द्र सरकार की नींद उड़ा दी। और अंततः जन–दबाव के चलते सरकार को खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का निर्णय स्थगित करना पड़ा।

दिल्ली

भारत के खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश की छूट देने के सरकार के फैसले का प्रबल विरोध करते हुए 1 दिसम्बर 2011 को दिल्ली प्रदेश भाजपा के 30 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं ने राजधानी की सभी प्रमुख बाजारों को बंद कराकर व्यापारियों के अभूतपूर्व भारत बंद में शिरकत की। दिल्ली की 20 प्रमुख बाजारों में आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के पुतले फूंके। प्रदेश प्रभारी श्री एम. वैंकेया नायडू ने करोलबाग में व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सरकार रिटेल में एफडीआई का फैसला तुरन्त वापस नहीं लेती तो इस जनविरोधी, व्यापार–विरोधी सरकार को जाना होगा। भाजपा भारत के व्यापारियों को तबाह होता नहीं देख सकती है।

करोलबाग में श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि अमेरिका के न्यूयार्क शहर में भी अमेरिकी सरकार ने वॉलमार्ट को अपने शोरूम खोलने की इजाजत नहीं दी है। क्या कारण है कि भारत सरकार यहां विदेशी कम्पनियों को कारोबार चलाने की छूट देने की जल्दी में है? प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री अमेरिका के दबाव में हैं इसी कारण उनको देश के खुदरा व्यापारियों की कोई चिंता नहीं है। सरकार ने विदेशी दबाव में खुदरा कारोबार में विदेशी कम्पनियों को भारत में कार्य करने की जो खुली छूट दी है, उसके परिणाम भयंकर होंगे। देश में ऐसी बेरोजगारी फैलेगी कि लाखों लोग सड़क पर आ जायेंगे। देश की सदियों पुरानी अर्थव्यवस्था ही डावांडोल हो जाएगी। परोक्ष रूप से भारत पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का राज कायम हो जाएगा। इतना बड़ा निर्णय करने से पहले कांग्रेस

सरकार ने अपनी ही पार्टी के लोगों तथा अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में नहीं लिया। इसी कारण कांग्रेस के लोग और सहयोगी दल भी इस निर्णय

का विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने शासन वाले राज्यों – छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड और बिहार में यह फैसला न लागू करने का जनहितकारी निर्णय किया है। प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने करोलबाग के अलावा उत्तम नगर, जंतर मंतर आदि स्थानों पर भी व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया। करोलबाग की जनसभा में राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल भी उपस्थित थे। उत्तम नगर में सरकार का पुतला फूंकने के बाद कार्यकर्ता अपने को रोक नहीं पाए और उन्होंने जनता के सहयोग से घंटों सड़क पर बैठकर धरना दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता ने जंतर मंतर, उत्तम नगर और करोलबाग में एकत्रित हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं तथा व्यापारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि खुदरा कारोबार में एफडीआई की छूट देकर सरकार ने जो देश विरोधी निर्णय किया है, उससे भारत की अर्थव्यवस्था में एक प्रकार की सुनामी आ जाएगी। व्यापार, उद्योग तथा कारोबार का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं बचेगा। डायनासोर की तरह से विदेशी कम्पनियां देश के परम्परागत् भारतीय उद्योग व्यापार को पूरी तरह बर्बाद कर देंगी। पुश्तैनी कारोबार करने वाले घराने तथा गली मौहल्लों के खुदरा व्यापारी पूरी तरह बेरोजगार हो जायेंगे। देश की अर्थव्यवस्था, यहां के उद्योग व्यापार पर विदेशी कम्पनियों का एकाधिकार (मोनोपोली) स्थापित हो जाएगा। एक तरह से भारत फिर से विदेशों के कब्जे में आ जाएगा। इसके दूरगामी भयंकर दुष्परिणाम होंगे। इस बारे में सरकार ने बगैर सोचे–समझे संसद के चलते समय में हड़बड़ी में यह फैसला किया है। अब भी समय है कि देशव्यापी विरोध को देखते हुए सरकार जाग जाए और रिटेल में एफडीआई की परमीशन वापस ले ले।

श्री गुप्ता ने बताया कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां वॉलमार्ट, कार्फू, मेट्रो, टेस्को जैसी बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों की नजर भारत के लाखों–करोड़ रूपए के खुदरा व्यापार पर कब्जा करने की बरसों से रही है। इसका कारण यह है कि देश का इस समय कुल खुदरा व्यापार जो 30 लाख करोड़ रूपया वार्षिक का है, वह अगले 20 सालों में बढ़कर 80 से 90 लाख करोड़ रूपया सालाना का हो जाएगा। इस प्रकार ये कम्पनियां एक ही देश भारत से उतना व्यापार करके खरबों रूपए का मुनाफा कमायेंगी जितना की वे विदेश के 20 देशों में भी व्यापार करके नहीं कमा पाती हैं। भारत में कुल खुदरा व्यापार का 61 प्रतिशत हिस्सा अनाज, दालें, फल, सब्जी, दूध, चाय, अंडा, कॉफी, मसाले, चिकन, गोश्त का है। यह सारा कारोबार इस समय भारत का असंगठित क्षेत्र का व्यापारी चलाता है।

सरकारी सर्वे के अनुसार भारत के प्रत्येक उपभोक्ता के घर से औसतन 200 से 280 मीटर की दूरी पर उपरोक्त सामान आसानी से लोकल दुकान पर कम कीमत में मिल जाते हैं। जब विदेशी कम्पनियां आ जायेंगी तो वे सबसे पहले इन्हीं छोटे व्यापारियों को खायेंगी क्योंकि अपनी मोनोपोली स्थापित करने के लिए वे लागत से भी कम कीमत पर घाटे में व्यापार करेंगी क्योंकि दो–तीन साल घाटा सहने से उनकी सेहत पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। देश के देशी व्यापार को तबाह करने के बाद वे अपनी मनमानी

शर्तों पर माल बेचेंगी और इसे खरीदने के लिए उपभोक्ता विवश होगा।

दिल्ली बंद में व्यापारियों तथा भाजपा कार्यकर्ताओं को पूर्व सांसद वरिष्ठ व्यापारी नेता श्री श्याम बिहारी मिश्रा ने भी सम्बोधित किया। टाउन हाल चांदनी चौक में जिलाध्यक्ष जय प्रकाश, मधुबन चौक रोहिणी में प्रदेश महामंत्री प्रवेश वर्मा तथा जिलाध्यक्ष रमेश चौहान, मधुबन चौक विकास मार्ग में पूर्व सांसद चेतन चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष पवन शर्मा तथा जिलाध्यक्ष निर्मल जैन, अजमलखां रोड करोलबाग में प्रदेश मंत्री राजन तिवारी, प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चाध्यक्ष कृष्ण लाल ढिलोड, राजेश भाटिया, एम–ब्लाक मार्केट ग्रेटर कैलाश में महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्षा शिखा राय, उपमहापौर अनिल शर्मा और जिलाध्यक्ष पंकज जैन, बाटा चौक सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर और इन्द्रा चौक न्यू कोंडली में रामचरण गुजराती, हमदर्द चौक में प्रदेश महामंत्री रमेश बिधूड़ी और जिलाध्यक्ष चौधरी छोटे राम, प्रेरणा चौक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मांगेराम गर्ग, प्रदेश महामंत्री आशीष सूद, जिलाध्यक्ष रेखा गुप्ता, खजूरी चौक में प्रदेश कार्यालय मंत्री महेन्द्र गुप्ता और जिलाध्यक्ष चौ. महक सिंह, मौजपुर चौक में प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल गोयल, विधायक नरेश गौड़ और जिलाध्यक्ष कैलाश जैन, पत्थर मार्केट मंगोलपुर गांव में संसार सिंह, रघुवीर नगर में प्रदेश उपाध्यक्ष आर.पी. सिंह तथा जिलाध्यक्ष राजीव बब्बर, उत्तम नगर चौक में सुमन प्रकाश शर्मा तथा महिपालपुर चौक में प्रदेश उपाध्यक्ष विशाखा शैलानी, सतीश उपाध्याय तथा जिलाध्यक्ष मनोज शर्मा के नेतृत्व में हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने घंटों प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला फूंका और नारे लगाए 'एफडीआई नहीं हटी तो – सरकार को हटना होगा', '20 करोड़ व्यापारियों को बर्बाद मत करो – मत करो', 'विदेशी कम्पनियां यदि आयेंगी तो देसी व्यापार को खायेंगी' आदि।

मध्य प्रदेश

प्रदेश में बंद का जबर्दस्त असर दिखाई दिया। प्रदेश के सभी थोक व बड़े बाजार बंद रहे। व्यापारिक संगठनों ने जगह–जगह केंद्र सरकार के पुतले जलाए एवं अपना विरोध प्रकट किया।

प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारिक शहर इंदौर में सभी बाजार बंद रहे। ग्वालियर व जबलपुर में भी बंद का व्यापक असर दिखाई दिया।

भोपाल में सभी थोक बाजार बंद रहे। बैरागढ़ कपड़ा व बर्तन बाजार, हनुमानगंज गल्ला मार्केट, सर्राफा बाजार, किराना बाजार बंद रहे। मेडिकल व्यापारी एसोसिएशन ने भी बंद को समर्थन दिया था। यहां नए भोपाल व भेल के फुटकर बाजार भी पूरी तरह बंद थे। प्राइवेट स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई थी। भोपाल में चेंबर आफ कामर्स समेत 37 संगठनों ने बंद को समर्थन दिया था। इंदौर भी पूरी तरह बंद रहा। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ ने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का पुतला जलाया। सियागंज में व्यापारियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पुतलों को फांसी पर लटकाया। ग्वालियर के ज्यादातर बाजार बंद रहे। यह बंद थोक व खुदरा बाजारों से लेकर सब्जी मंडी तक नजर आया। यहां तक कि स्कूल व कालेज भी बंद रखे गए। यह बंद शांतिपूर्ण रहा एवं किसी प्रकार का उपद्रव देखने को नहीं मिला।

उत्तर प्रदेश

भारत बंद के तहत उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। बंद के समर्थन में हजरतगंज, चौक, आलमबाग, अमीनाबाद जैसे प्रमुख बाजारों के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। लखनऊ के करीब दो लाख से ज्यादा छोटे–बड़े व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद करके भारत बंद का समर्थन किया। आगरा में भी राष्ट्रव्यापी बंद का असर देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर ज्यादातर व्यापारी बंद में शामिल हुए।

राजस्थान

बंद के दौरान राजस्थान के सभी छोटे–बड़े शहरों के बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। छोटी–बड़ी सभी दुकानें पूरी तरह बंद रही। असल में व्यापारी घरों से निकले ही नहीं। 30 नवम्बर को ही व्यापारिक संगठनों ने संयुक्त बैठक कर पूरी तरह बंद रखने का फैसला कर लिया था। इस बंद का असर यह है कि हर बार की तरह छोटी–छोटी चाय व खान–पान की दुकानें भी नहीं खुली। भारत बंद का उदयपुर में सुबह से व्यापक असर नजर आया। शहर के व्यापारियों द्वारा स्वेच्छा से अपना कारोबार बंद रखने से शहर में सुबह से ही राष्ट्रव्यापी आह्वान का असर नजर आने लगा। बड़े शोरूम के साथ चाय दुकानें भी बंद रही। बंद समर्थकों ने

चिकित्सा सेवाओं के बंद से मुक्त रखा। जोधपुर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने महंगाई व एफडीआइ के विरोध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला फूंका। इन लोगों का आरोप था कि कांग्रेस सरकार की वजह से आमजन पहले ही महंगाई से त्रस्त है, अब विदेशी निवेश आने से लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जाएंगे। भाजपा के बैनर तले व्यापारियों ने सड़क पर निकलकर सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में नारे लगाए। बड़े शहरों के अलावा भी सभी शहरों में बंद का असर देखने को मिला। स्कूलों व अस्पतालों को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान व बाजार पूरी तरह बंद रहे।

महाराष्ट्र

मुंबई सहित महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में करीब 35 लाख छोटे और मझोले व्यापारियों ने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के खिलाफ अपनी दुकानें बंद रखीं। फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (एफएएम) के अध्यक्ष मोहन गुरनानी ने बताया, 'हमें मुंबई और नवी मुंबई में बंद का अच्छा असर देखने को मिला क्योंकि कृषि उत्पाद बाजार समिति के व्यापारी एक दिन के बंद के समर्थन में शामिल हुए।'

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में खुदरा व थोक विक्रेताओं की दुकानें बंद रहने से व्यापार पर गहरा असर दिखा। केंद्र सरकार के खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति के फैसले के विरोध में आयोजित राष्ट्रव्यापी बंद का यहां काफी असर दिखा। कोलकाता का व्यवसायिक केंद्र माना जाने वाला बुर्रा बाजार सुनसान दिखा। इसे एशिया के सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक माना जाता है। यहां के व्यापारियों ने अपनी दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखकर बंद में हिस्सा लिया। सड़कों के किनारे स्थित दुकानें भी बंद रहीं। दवा की दुकानों और होटलों को इस बंद से बाहर रखा गया था।

झारखंड

विभिन्न व्यापारिक संगठनों और भाजपा सहित विपक्षी दलों के आह्वान पर आयोजित भारत बंद के साथ समूचे झारखंड में दुकानें एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे गए। रांची में सुबह से ही विभिन्न क्षेत्रों में गाड़ियों का आना–जाना बहुत सीमित था। दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे। सुबह से ही शहर के मुख्य मार्ग, सर्कुलर रोड, हीनू, कांके रोड, कोकर क्षेत्र, हटिया, हरमू, रातू रोड, कडरू आदि इलाकों में कोई भी दुकान एवं अन्य प्रतिष्ठान नहीं खुले।

बिहार

खुदरा व्यापार में एफडीआई के विरोध में डाक बंगला चौराहे पर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। पटना, लखीसराय, भागलपुर, जहानाबाद सहित अन्य कई जिलों में बंद का असर देखा गया। भाजपा, स्वदेशी जागरण मंच और कुछ अन्य मजदूर संघों ने व्यापारियों के साथ मिलकर रैलियां निकालीं।

उत्तराखंड

बंद का उत्तराखंड के अलग–अलग जिलों में व्यापक असर देखा गया। राज्य के अलग–अलग जिलों से मिली रिपोर्ट के अनुसार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्कूल, दुकानें और पेट्रोल पंप भी बंद रहे। सडकों पर यातायात काफी कम था। राज्य के चमोली, उत्तरकाशी, पौडी, टिहरी, पिथौरागढ, अल्मोडा, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित अन्य जिलों से मिली रिपोर्ट के अनुसार बंद का व्यापक असर देखा गया। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद कर रखा था। कई स्थानों पर व्यापारियों ने केन्द्र, सरकार के इस निर्णय के खिलाफ नारेबाजी भी की। देहरादून में बंद के दौरान पल्टनबाजार, धामावाला, घंटाघर, चकराता रोड, सर्वे चौक, राजपुर रोड, डालनवाला सहित अन्य क्षेत्रों की अधिकांश दुकानें बंद रहीं।

कर्नाटक

राज्य में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखीं। कर्नाटक में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं और मल्टी ब्रैंड रिटेल सेक्टर में एफडीआई की अनुमति देने के केन्द्र के निर्णय का विरोध किया। शहर में प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों पर दुकानें बंद रहीं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी बंद का असर रहा।

ओडिशा

राजधानी भुवनेश्वर, कटक, बरहामपुर, संबलपुर, राउरकेला और बालेश्वर सहित कई स्थानों पर बंद का असर देखा गया। ■

कांग्रेस-शासन में अमीरों के लिए जगमगाता भारत और गरीबों के लिए अंधकारमय भारत : आडवाणी

3 दिसम्बर 2011 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप सम्मिट' में 'भविष्य की दिशा में 'भारत की यात्रा' विषय पर श्री लालकृष्ण आडवाणी का भाषण

मुझे हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप सम्मिट में भाग लेने पर हार्दिक प्रसन्नता है। हाल के वर्षों में इस प्रकार की अनेक बैठकें और शिखर सम्मेलन होने लगे हैं जिनमें विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के लोग तथा विभिन्न विचारधारा वाले नेताओं को पारस्परिक विचारविमर्श करने का एक मंच मिल जाता है। किन्तु 'हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप सम्मिट' ने इस क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बना लिया है।

मुझसे 'इण्डियाज यात्रा इंटू दि फ्यूचर' अर्थात् 'भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा' पर बोलने के लिए कहा गया है। सम्भवतः इस सम्मेलन के आयोजकों ने सोचा होगा कि यात्रा विषय पर मुझे बोलने का अवसर देना उचित होगा जो निरंतर यात्री बने रहते हैं। मुझे लगता है यह ठीक ही है। दरअसल, अभी पिछले पक्ष में ही मैंने अपने राजनीतिक जीवन की छठी राष्ट्रव्यापी यात्रा सम्पन्न की है। इसका नाम था 'जन चेतना यात्रा'। इस यात्रा को सड़क द्वारा 40 दिनों में पूरी करे हुए मुझे अपने विशाल देश के हर वर्ग से मिलने का मौका मिला। सच यह है कि इन यात्राओं से मुझे अमूल्य जानकारी प्राप्त होती है, जिससे मैं देश की राजनीति की कहीं अधिक प्रभावकारी सेवा करने में समर्थ हो पाता हूं।

वास्तव में, मैं आपको बताऊं कि इन यात्राओं के दौरान मुझे 'भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा' के व्यापक विषय से जुडे कई महत्वपूर्ण उप-विषयों या सम्बन्धित विषयों पर बोलने का अवसर मिला है। 1990 की 'रामरथ यात्रा' में ऐसी बुनियादी धारणाओं और व्यावहारिकताओं के प्रश्न थे, जो आज तक 'सेक्युलरिज्म' के नाम पर चले आ रहे हैं।

इसमें भारतीय राष्ट्रवाद का मर्म क्या है, उसकी समझ को जानकर उसकी विकृतियों को सुधारने का प्रयास रहता है। क्योंकि मेरा मानना है कि जिस राष्ट्र के पास अपने पुरातन का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, वह अपने लिए सही भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है।

इसी प्रकार, 1997 की मेरी स्वर्ण जयन्ती यात्रा, जो संयोग से भारत की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हुई, के भी दो लक्ष्य थे। पहला इसका उद्देश्य हमारे गौरवपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के सभी बहादुर नायकों का सम्मान करना। दूसरा, जो की उतना ही महत्वपूर्ण था कि लोगों को 'स्वराज को सुराज' में परिवर्तित करने के लिए जाग्रत करना।

1997 से, मेरी सभी राजनीतिक गतिविधियों और आंदोलनों में 'सुराज'

को मैंने निरंतर प्रमुख स्थान पर रखा है। यही बात मेरे इस नवीनतम यात्रा में प्रमुख बिन्दु बनी रही। किन्तु, 'जन चेतना यात्रा' में एक बात और भी प्रमुख बनी, वह थी 'स्वच्छ राजनीति'।

मुझे अपनी यात्राओं का संक्षिप्त प्रसंग इसलिए देना पड़ा क्योंकि आपने आज मेरे प्रमुख भाषण से इनका सम्बन्ध है। बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि छह दशकों की मेरी राजनीतिक यात्रा के दौरान भारत का भविष्य ही मेरा मार्गनिर्देश करता रहा है। परन्तु, आगे बढ़ने वाली किसी भी यात्रा में पीछे छूट गए पथ की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। कोई भी अच्छा संवाहक जानता है कि आगे बढ़ते हुए न केवल उसे आगे का दृश्य साफ दिखाई पड़ना चाहिए, बल्कि उसे शीशे से पीछे के रास्ते की भी सुध रहनी चाहिए।

मित्रों, अब मैं आपके सामने सीधे अपने विचार प्रस्तुत करूं जो मेरे विचार में 'भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा' का निर्देशन करते हैं।

भारत का पश्चिमी देशों के विकास मॉडलों की नकल करना जरूरी नहीं

पहली बात, मैं जानना चाहूंगा कि हमें क्यों विकास के पश्चिमी मॉडल की बिना सोचे समझे नकल करनी चाहिए, जबकि हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यह मॉडल कभी भी स्थायी नहीं रहा है, बल्कि हमने देखा है कि इससे पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस चुकी है? क्या भारत को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करना चाहिए, जिसके लिए वह अन्य देशों के सकारात्मक अनुभवों से सीख ले सकता है और उनकी गलतियों से बच सकता है? क्या अमरीका और यूरोप के विकास का मॉडल भारत के विकास के लिए प्रतिरूप बन सकते हैं?

उदाहरण के लिए खुदरा व्यापार में एफडीआई को ले। इससे हमारे समाज के कितने लोगों को लाभ मिल सकेगा? ऐसा क्यों है कि मुद्रास्फीति, महंगाई और बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्याओं से जूझने के लिए, जिनका निर्माण खुद सरकार ने अपने कुशासन से पैदा किया, खुदरा व्यापार जैसे क्षेत्र में विदेशी निवेश की तलाश में हमारी सरकार क्यों भटक रही है? खुदरा व्यापार में एफडीआई से लाखों नौकरियों और मुद्रास्फीति कम करने की बात कह कर यूपीए सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। यह सब कुछ लीपा–पोती मात्र है।

सरकार लाखों दुकानदारों और देश के एसएमई की आशंकाओं को दूर करने में विफल रही है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी का अपना मजदूर संघ 'इंटक' भी सरकार के प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। हाल के दशकों में खुदरा व्यापार पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के सरकार के फैसले के विरूद्ध पिछले बृहस्पतिवार को हुआ पूर्ण 'भारत बंद' हाल के पिछले दशकों में कभी देखने को नहीं मिला।

इसी प्रकार के लम्बे चौड़े दावे तीन वर्ष पहले भी भारत–अमरीका–न्यूक्लियर सौदे के अवसर भी किए गए थे। तब संसद में सरकारी नेताओं ने कहा था कि इससे भारत की दुर्दांत बिजली कमी समस्या सुलझ जाएगी। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं: 'पिछले तीन वर्षों में कितने नए न्यूक्लियर संयंत्रों पर काम शुरू हुआ है? अगले दस वर्षों में समुचित आधार पर ही कितनी न्यूक्लियर बिजली पैदा होगी? क्या सरकार इस मुद्दे पर श्वेत पत्र निकालेगी?''

कांग्रेस ने अमीरों के लिए जगमगाता भारत और गरीबों के लिए अंधकारमय भारत का निर्माण किया

दूसरी बात, भारत को भविष्य में ऐसी दिशा की ओर बढ़ना चाहिए जिससे हमारा समाज अधिक समतावादी बने। सभी 1.2 बिलियन भारतीयों के व्यापक रूप से समान अवसर प्राप्त हो सकें। दुख की बात है कि आज भारत पहले से कहीं अधिक विषमता की ओर बढ़ा है। हमारे समाज के कुछ लोग तो हाल के वर्षों में बेहद समृद्ध हुए हैं और अधिकांश लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और यहां तक कि बुनियादी आवश्यकता पीने का पानी भी नसीब नहीं है। जब मैंने 2004 में भारत उदय यात्रा निकाली थी तो वे लोग, जो आज सरकार में हैं, उन्होंने 'शाइनिंग इण्डिया' के दावे पर मेरी आलोचना की थी। मैं 'शाइनिंग इण्डिया' के बारे में कोई दावा नहीं करता। मेरा दावा तो 'राइजिंग इण्डिया' था, जिसका सही अनुवाद 'भारत उदय' है। मेरी गलती यह थी कि मैंने इसे 'शाइनिंग इण्डिया' कहने

हमें क्यों विकास के पश्चिमी मॉडल की बिना सोचे समझे नकल करनी चाहिए, जबकि हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यह मॉडल कभी भी स्थायी नहीं रहा है, बल्कि हमने देखा है कि इससे पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस चुकी है? क्या भारत को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करना चाहिए, जिसके लिए वह अन्य देशों के सकारात्मक अनुभवों से सीख ले सकता है और उनकी गलतियों से बच सकता है? क्या अमरीका और यूरोप के विकास का मॉडल भारत के विकास के लिए प्रतिरूप बन सकते हैं?

की अनुमति दी। परन्तु मैं अपने विरोधियों से पूछना चाहूंगा कि ''पिछले सात वर्षों में आपकी गलत नीतियों के कारण बहुत अमीर लोगों के एक छोटे से वर्ग के लिए भारत को जगमगाता और भडकीला भारत बना दिया जब कि गावों में रहने वाले अधिकांश लोग, नगरों की गंदी बस्तियां और मध्यवर्गीय लोगों को अधंकार में भटकने के लिए छोड़ दिया है।''

अतः, यदि हम भविष्य में भारत की यात्रा को सही दिशा में बढ़ाना चाहते हैं, तब यदि हमें भारत के करोड़ों युवकों को अपना उज्ज्वल भविष्य बनाने की आशा प्रदान करनी है तो हमें अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों में तुरंत ही सुधार करना आवश्यक है। हमें सुधार प्रक्रिया का पूर्णतः सुधार करना होगा।

तीसरी बात, राजनीति और सरकार में मेरे लम्बे अनुभव ने मुझे बताया है कि सही ठोस–नीतियों की अपेक्षा सही शासन का कहीं अधिक महत्व है। स्वतंत्रता के बाद, विशेष रूप से पिछले 30–40 वर्षों के बाद सुशासन के आचरणों और मूल्यों में धीरे–धीरे गिरावट होती चली गई है। सत्ताधारी पार्टी द्वारा दलगत स्वार्थों के लिए आरम्भ से लेकर शिखर पर बैठे लोगों ने शासन के संस्थानों के दुरूपयोग को हर स्तर पर फैलाया है।

भ्रष्टाचार का कैंसरयुक्त विस्तार 'सुराज' के अभाव के कारण ही तो दिखाई पड़ता है। हम इस रोग से कभी समझौता नहीं कर सकते क्योंकि यही हमारी राजनीति और समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। परन्तु इसकी साफ–सफाई शिखर से आरम्भ होनी चाहिए।

भारत के इतिहास में जिन लोगों के नाम भ्रष्टाचार के बड़े–बड़े घोटालों से जुड़े हैं और जो अब भी सरकार में उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं, उन्हें इन पदों पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

स्वतंत्र भारत का निकृष्टतम घोटाला

इन दिनों, विशेष रूप से संसद में पेश कैग की रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हुए टेलीकॉम मंत्रालय पर 1.76 लाख करोड़ रूपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ, जिससे आम नागरिक 2जी स्पैक्ट्रम को आज तक प्रकाश में आने वाला सबसे बड़ा घोटाला मानते हैं।

fu%lng] dx dk ;g vuekfur udlku dk vk;ke grcf) dju okyk gA ijUr tc ge ?kkVky d ifj.kkek vkj iÑfr ij fopkj djr g rk ge ^ukV d cny okV* ?kkVky dh rqyuk e vkj Hkh vfèkd l?kkrd ?kkVky dh dYiuk ugh dj ldr g] ftlu tqykbZ 2008 e fo'okler thru d fy, ;wih, ljdkj dk cpk, j[kk] gkykfd ;g ljdkj dE;qfuLV Cykd }kjk Hkkjr&vejhdk U;qfDy;j le>kr d f[kykQ ;wih, ljdkj l leFkZu okil yu d ckn vYier e vk xbZ FkhA fojk/kh i{k d 19 lklnk dk djkM+k :i, dh ?kl nh xbZ vkj mUgkau ljdkj d i{k e okV fn;kA

XXX

भ्रष्टाचार के विरूद्ध 40 दिन की जन चेतना यात्रा को मैंने पिछले माह ही पूरा किया है, जो एक तरह से 'नोट के बदले वोट' की खातिर शुरू की गई थी।

2008 में विश्वासमत के दौरान इस घोटाले का पर्दाफाश तीन भाजपा सांसदों–फग्गनसिंह कुलस्ते, महावीर भगौरा और अशोक अर्गल ने किया था। कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए उन्हें खरीदने के लिए कैश के बण्डल लेकर ये तीन सांसद सीधे पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और उन्होंने टीवी कैमरों के सामने उन्हें पूरे विश्व को दिखाया।

6 सितम्बर 2011 को, पार्लियामेंट के मानसून सत्र की समाप्ति से दो दिन पूर्व कुलस्ते और भगौरा को गिरफ्तार किया गया और उन्हें तिहाड जेल भेजा गया। इससे मैं अत्यंत दुःखी हुआ। 8 सितम्बर 2011 को, स्पीकर की अनुमति से सत्र के आखिरी दिन मैंने लोकसभा में इस घटना पर अपना भारी आक्रोश व्यक्त किया।

विश्व के लोकतांत्रिक देशों में मैंने देखा है कि जो लोग इस प्रकार के घोटालों का पर्दाफाश करते हैं, उन्हें 'व्हिसल ब्लोअर' का नाम दिया जाता है और उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है। मैं जानता था कि मेरी पार्टी के इन सांसदों की मंशा क्या थी।

राजनीति और सरकार में मेरे लम्बे अनुभव ने मुझे बताया है कि सही ठोस–नीतियों की अपेक्षा सही शासन का कहीं अधिक महत्व है। स्वतंत्रता के बाद, विशेष रूप से पिछले 30–40 वर्षों के बाद सुशासन के आचरणों और मूल्यों में धीरे–धीरे गिरावट होती चली गई है। सत्ताधारी पार्टी द्वारा दलगत स्वार्थों के लिए आरम्भ से लेकर शिखर पर बैठे लोगों ने शासन के संस्थानों के दुरूपयोग को हर स्तर पर फैलाया है।

मैं उनका नेता था। यदि मेरा विचार यह होता कि उनका करेंसी नोटों का सदन में लहराना गलत कार्य होगा तो मैं उन्हें रोक देता।

यदि सरकार सोचती है कि उनका यह कार्य कानूनन गलत है तो मेरे विचार में मैंने उनसे भी बड़ा गलत कार्य किया है और मुझे तिहाड़ भेज देना चाहिए था, न कि उन लोगों को जिन्होंने 'व्हिसल ब्लोअर' का काम कर लोकतंत्र की अनूठी सेवा की है। मैं मानता हूं कि यह घूस के माध्यम से जीता गया विश्वास मत है। सरकार ने भारतीय लोकतंत्र के उज्ज्वल नाम को कलंकित किया है।

उसके तुरंत बाद, मैंने एक प्रेस सम्मेलन बुला कर भ्रष्टाचार, काला धन और महंगाई के विरूद्ध देशभर की व्यापक यात्रा की अपनी योजना की घोषणा की।

XXX

इस सप्ताह बृहस्पतिवार को बर्लिन की एक सिविल सोसाइटी आर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नवीनतम 'करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स' जारी किए हैं।

निगरानी रखने वाली इस इंटरनेशनल के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से भारत की छवि निरंतर धूमिल होती जा रही है।

विश्व के लोकतांत्रिक देशों में मैंने देखा है कि जो लोग इस प्रकार के घोटालों का पर्दाफाश करते हैं, उन्हें 'व्हिसल ब्लोअर' का नाम दिया जाता है और उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है। मैं जानता था कि मेरी पार्टी के इन सांसदों की मंशा क्या थी। मैं उनका नेता था। यदि मेरा विचार यह होता कि उनका करेंसी नोटों का सदन में लहराना गलत कार्य होगा तो मैं उन्हें रोक देता। यदि सरकार सोचती है कि उनका यह कार्य कानूनन गलत है तो मेरे विचार में मैंने उनसे भी बड़ा गलत कार्य किया है और मुझे तिहाड़ भेज देना चाहिए था, न कि उन लोगों को जिन्होंने 'व्हिसल ब्लोअर' का काम कर लोकतंत्र की अनूठी सेवा की है। मैं मानता हूं कि यह घूस के माध्यम से जीता गया विश्वास मत है। सरकार ने भारतीय लोकतंत्र के उज्ज्वल नाम को कलंकित किया है।

2007 में भारत का 180 देशों में 72वां दर्जा था। पिछले वर्ष, यह 87वां हो गया। इस वर्ष, 183 देशों में से इसका दर्जा 95वें तक जा पहुंचा।

XXX

इतना समझ लेना चाहिए कि 'सुराज और भ्रष्टाचार' दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार, मैं इस बात पर भी बल देना चाहूंगा कि 'लोकतंत्र और परिवारवाद' साथ–साथ नहीं रह सकते हैं।

सिद्धांत रूप से मुझे विश्वास है कि कम से कम किसी को भी उपर्युक्त उल्लेख के प्रथम भाग पर विवाद नहीं होगा। परन्तु, मैं चाहता हूं कि सत्ताधारी पार्टी इस उल्लेख के दूसरे भाग की यथार्थता को समझे।

XXX

'भविष्य की दिशा में भारत की अपनी यात्रा' के लिए सुराज, स्वच्छ राजनीति और प्रभावशाली लोकतंत्र आदर्श वाक्य होने चाहिए।

ये मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस अवसर पर बांटना चाहता था। मैं पुनः हिन्दुस्तान टाइम्स का मुझे इस 'सम्मिट' में भाग लेने के लिए आमंत्रण देने पर आभार व्यक्त करता हूं।

धन्यवाद। ■

देश के 51 करोड़ लोगों की रोजाना की कमाई मात्र 75 रुपये

केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों के उत्थान व उनकी आर्थिक दशा में सुधार के बड़े– बड़े दावे भले ही करें, लेकिन हकीकत यह है कि भारत में गत तीन दशकों में आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं। विभिन्न तबकों की आमदनी के बीच फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमीरों की आमदनी गरीबों की आमदनी से 12 फीसदी ज्यादा है। देश की एक अरब इक्कीस करोड़ की आबादी के 42 फीसदी हिस्से (तकरीबन 51 करोड़ लोग) की एक दिन की आमदनी आज भी महज 1.25 डॉलर (करीब 75 रुपये) ही है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के महासचिव एंजल गुरिया द्वारा पेरिस में जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में समानतावादी कहलाने वाले मुल्कों में गरीब–अमीर के बीच का फासला बढ़ा है। दुनिया के 10 फीसदी अमीरों की आमदनी गरीबों की तुलना में 9 गुना ज्यादा है। चीन और मेक्सिको में अमीरों की आमदनी गरीबों की आमदनी से 25 प्रतिशत ज्यादा है। ओईसीडी ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर अपनी रिपोर्ट में भारत,चीन, अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया, रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का आकलन किया है। इन सात देशों में से भारत में गरीबी दर सबसे ज्यादा है, जहां 42 फीसदी आबादी की प्रतिदिन की आमदनी मात्र 1.25 डॉलर है। ■

अपने जाल में फंसी सरकार

केंद्र सरकार खुदरा कारोबार में एफडीआई के मुद्दे पर देशहित के नुकसान को क्यों नजरंदाज कर रही है?

& v#.k tsVyh

संप्रग सरकार एक बड़े संकट का सामना कर रही है। मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी देने का फैसला सरकार ने गलत समय पर लिया – देश की आर्थिक सच्चाइयों के लिहाज से भी और मौजूदा राजनीतिक स्थिति के लिहाज से भी। इस फैसले के समय पर प्रत्येक राजनीतिक प्रेक्षक को आश्चर्य होगा। सरकार की विश्वसनीयता अपने सबसे निचले स्तर पर है। सरकार का नेतृत्व भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन के आरोपों का जवाब दे पाने में असफल रहा है। संसद का एजेंडा पहले ही ऐसे मसलों से भरा पड़ा था जो सरकार के लिए परेशानी का कारण बनते। अत्यंत कठिनाई से सरकार ने मूल्यवृद्धि पर मतदान वाले प्रस्ताव से खुद का बचाव किया और वह काले धन तथा भ्रष्टाचार पर मतदान वाले प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सहमत हुई। संसद सत्र के बीच में ही कैबिनेट ने मल्टीब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने का फैसला कर लिया। इस फैसले के पीछे क्या राजनीतिक बाध्यता थी?

रिटेल में विदेशी निवेश आने का एक अन्य बड़ा प्रभाव उत्पादन क्षेत्र पर पड़ेगा। हमारे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अब तक सुधार नहीं हो सके हैं। हमारी ब्याज दरें बहुत ऊंची हैं, बुनियादी ढांचा खराब हालत में है, बिजली सरीखी जरूरतें महंगी हैं और व्यापार की सुविधाएं भी अस्त–व्यस्त हालत में हैं। जब तक हम इन क्षेत्रों में सुधारों की गाड़ी आगे नहीं बढ़ाते हैं तब तक हम चीन के समान कम लागत वाला उत्पादन नहीं कर सकते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने यह प्रदर्शित किया है कि उसने आर्थिक सुधारों की राह छोड़ दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यावसायिक जगत का विश्वास इसी कारण डगमगा रहा है। पिछले तीन वर्षों से मुद्रास्फीति अनियंत्रित रही है। पेट्रोल की कीमतें भी नई ऊंचाई पर पहुंच रही हैं। इसका एक कारण जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना है वहीं दूसरा कारण पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले ऊंचे कर भी हैं। बुनियादी ढांचे का विकास भी धीमा पड़ चुका है। देश में निवेश का माहौल भी सही नहीं है। राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है और जीडीपी विकास दर इस वर्ष घटने के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ न कर पाने के कारण आलोचना का सामना कर रही सरकार ने अचानक मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति देने का बड़ा फैसला कर लिया। सरकार के इस फैसले ने विपक्षी दलों को भी एकजुट कर दिया है। संप्रग के दो प्रमुख सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस तथा द्रमुक भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखते हुए सपा और बसपा के पास भी इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं कि वे सरकार के फैसले के खिलाफ खड़ी हों। इस मसले पर संसद में संख्याबल निश्चित रूप से सरकार के साथ नहीं है। सच तो यह है कि सरकार अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई है और उसे

बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अगर वह इस फैसले से पीछे हटती है अर्थात् रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेश को अनुमति देने का फैसला वापस लिया जाता है तो प्रधानमंत्री की साख चली जाएगी। अगर वह इस मसले पर मतदान की व्यवस्था वाले स्थगन प्रस्ताव के लिए राजी होती है तो उसकी हार सुनिश्चित है। सरकार मतदान में पराजय का जोखिम नहीं उठा सकती इसलिए उसकी पूरी ऊर्जा द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस को मनाने में लगी है ताकि वे उसे इस स्थिति से उबार लें। छोटे खुदरा व्यापारी बंगाल की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक हैं। व्यापारी परंपरागत रूप से माकपा के विरोधी रहे हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस सरकार के समर्थन में खड़ी होती है तो वह व्यापारियों का मत माकपा को उपहार में दे देगी।

संसद विपक्षी दलों के कारण ठप नहीं पड़ी है, बल्कि सच यह है कि सरकार खुद ही कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही है। अगर इस फैसले पर होने वाले मतदान में सरकार की हार होती है अथवा उसे अपना फैसला वापस लेना पड़ता है तो सरकार को वाकई तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। आज संप्रग सरकार एक ऐसी स्थिति में आ फंसी है कि उसे दोनों ही स्थितियों में हार नजर आ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का चरित्र ऐसा है कि मल्टी ब्रांड में विदेशी निवेश निश्चित ही अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाएगा। भारत में केवल 18 प्रतिशत श्रम संगठित अवस्था में है। 30 प्रतिशत या तो बेरोजगार हैं या आकस्मिक श्रमिक की श्रेणी में आते हैं, जबकि 51 प्रतिशत स्व–व्यवसाय में हैं। स्व–रोजगार की श्रेणी में सबसे बड़ा योगदान कृषि का है। चार करोड़ से अधिक भारतीय रिटेल कारोबार में लगे हुए हैं। साफ है कि रिटेल कारोबार अपने देश में रोजगार देने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से है। संगठित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मौजूदा रिटेल सेक्टर में लगे लोगों की आजीविका छीन लेगा। यह कड़वी सच्चाई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी देखी जा रही है। यही कारण है कि अमेरिका सरीखा विकसित देश भी वालमार्ट सरीखी कंपनियों को अपने रिटेल सेक्टर में उतरने की अनुमति नहीं दे रहा है।

जब राजग केंद्र की सत्ता में था तो हमें भी पश्चिमी शक्तियों की इस मांग का सामना करना पड़ा था कि रिटेल सेक्टर को विदेशी निवेश के लिए खोला जाए, लेकिन हमने दबाव का सामना किया। इस पर राष्ट्रीय सहमति बनी कि अभी इसके लिए सही समय नहीं आया है। सरकार इस सहमति के खिलाफ चली गई है। उचित यही है कि सरकार अपने कदम पीछे खींचे।

रिटेल में विदेशी निवेश आने का एक अन्य बड़ा प्रभाव उत्पादन क्षेत्र पर पड़ेगा। हमारे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अब तक सुधार नहीं हो सके हैं। हमारी ब्याज दरें बहुत ऊंची हैं, बुनियादी ढांचा खराब हालत में है, बिजली सरीखी जरूरतें महंगी हैं और व्यापार की सुविधाएं भी अस्त–व्यस्त हालत में हैं। जब तक हम इन क्षेत्रों में सुधारों की गाड़ी आगे नहीं बढ़ाते हैं तब तक हम चीन के समान कम लागत वाला उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उपभोक्ता वे उत्पाद खरीदेंगे जो सस्ते हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अपने उत्पादों की बिक्री की संभावनाएं अच्छी होंगी। इसका असर हमारे उत्पादन क्षेत्र पर पड़ेगा।

यह तर्क भी वास्तविक नहीं प्रतीत होता है कि रिटेल कारोबार में एफडीआई आने से बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और खेत से स्टोर तक उत्पादों के पहुंचाने में आने वाली लागत भी कम हो जाएगी तथा इसका फायदा भी किसानों को मिलेगा। इस संदर्भ में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि गन्ना किसान अपने उत्पाद खेतों से चीनी मिलों तक स्वयं ही पहुंचाते हैं और इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होती। यदि सरकार समर्थन मूल्य के रूप में उन्हें उनके उत्पादों के लिए सुरक्षा न दे तो बाजार की शक्तियां उनके शोषण में पीछे नहीं रहतीं। सवाल यह भी है कि यदि सरकार की दलील सही है तो बड़े रिटेल चेन वाले देश अपने किसानों को सब्सिडी क्यों दे रहे हैं ? यूरोप और अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी दे रहे हैं। क्यों रिटेल चेन अकेले ही उनका कल्याण नहीं कर पा रहे हैं ? रिटेल में एफडीआई के संदर्भ में यह जो उदाहरण दिया जा रहा है कि चीन को इससे लाभ हुआ है वह भी पूरी तरह सही नहीं है। चीन ने रिटेल में एफडीआई को अनुमति देने के पहले खुद को सस्ते 'मैन्युफैक्चरिंग' क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंतरराष्ट्रीय 'रिटेलरों' के लिए चीनी उत्पादों की बिक्री करना जरूरी हो गया। जब राजग केंद्र की सत्ता में था तो हमें भी पश्चिमी शक्तियों की इस मांग का सामना करना पड़ा था कि रिटेल सेक्टर को विदेशी निवेश के लिए खोला जाए, लेकिन हमने दबाव का सामना किया। इस पर राष्ट्रीय सहमति बनी कि अभी इसके लिए सही समय नहीं आया है। सरकार इस सहमति के खिलाफ चली गई है। उचित यही है कि सरकार अपने कदम पीछे खींचे। ■

(लेखक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं)

भारतीय राजनीति के गौरव हैं अटलजी

çHkkr >k

Xवालियर वीरांगना की समाधि स्थली है। ग्वालियर महान संगीतज्ञ तानसेन की जन्मस्थली और कर्मस्थली है। ग्वालियर के मानसिंह का किला और गुरु नानक दाता बन्दीछोड़ गुरूद्वारा की अमर कहानियों से जुड़ी गाथाएं अजर–अमर हैं। इतिहास के पन्नों में 'ग्वालियर' एक नहीं अनेक स्थानों पर स्वर्णाक्षरों मे वर्णित है। राजा–महाराजाओं की बात आए तो भला सिंधिया राज घराना को कोई कैसे भूल सकता है। पर इन सबसे हटकर ग्वालियर की धरती पर एक ऐसा गुदड़ी का लाल पैदा हुआ जिसने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से भारत का नाम विश्व में स्वर्णाक्षरों में लिख दिया। एक सामान्य शिक्षक के घर में पैदा हुए उस असामान्य व्यक्तित्व का नाम है प्रखर राष्ट्रवादी भारतमाता के सपूत पं. अटल बिहारी वाजपेयी। ''25 दिसम्बर'' को भारतीय जनता पार्टी ने 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अटल जी की उदारता को समझने की जो लोग कोशिश करना चाहे वह सिर्फ इस वाक्य से समझ सकते हैं ''जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान''। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था ''जय जवान, जय किसान''। अटलजी प्रधानमंत्री बने तो उन्होने यह नहीं कहा कि यह नारा हटा दो बल्कि उन्होंने कहा कि इसके आगे एक शब्द और जोड़ दो ''जय विज्ञान''। ''जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान'' इसे उदारता और राजनैतिक श्रेष्ठता का अद्वितीय उदाहरण माना जा सकता है।

~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~

'अटलजी' संसद के गौरव हैं तो वे गांव के ग्रामीणों की आत्मा की आवाज भी हैं। वे कुल देवता हैं। वे ग्राम देवता हैं। वे शीतल छायेदार वृक्ष हैं। वे मित्रों के मित्र हैं ही पर जो उन्हें अपना नहीं मानते उसे भी वे अपना लेते हैं। वे राजनीति की आस्था और निष्ठा हैं। वे राजनीति में 'विश्वास' हैं। वे राजनीति में मर्यादा के पालक हैं। वे शालीनता और विनम्रता के पुंज हैं। वे 'वरद्' पुंज हैं। वे शब्दों के साधक हैं और भारत मां के आराधक हैं। उनकी रग–रग में भक्ति और जनशक्ति है।

ग्वालियर के वे 'गौरवदीप' हैं। वहीं भारत के वे 'अमोल रत्न' हैं। वे अस्वस्थ हैं। उनका संपर्क अब किसी से नहीं है। काफी समय हो गया उनकी सभा सुनें। 'वाणी' में प्राण और प्राण में 'प्रण' लेकर बिरले लोग ही पैदा होते हैं। अटलजी से जुड़ी अनेक स्मृतियां करोड़ों लोगों के स्मृति पटल पर आज भी अजर–अमर हैं। लगता है कल ही की तो बात है, अटलजी से मिलकर आए थे। वे शहरों में रहने के आदि नहीं रहे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे पर इसके उलट देशवासी वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि कब बनेंगे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी।

'अटलजी' भारतीय राजनीति का वह नाम जिस पर एक दल भाजपा नहीं बल्कि जिस पर भारत गौरव करता है। संसद में मैं पहले संसदीय कार्यालय में था अब संसद में हूं, तब से लेकर आज भी अटलजी सेंट्रल हॉल से लेकर दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्यों की जुबां पर छाए रहते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता है जब अटलजी की चर्चा नहीं होती हो। हम कोने में बैठकर सुनते रहते हैं कि अरे अटलजी से हम लोग मिलने गए थे, बड़ा मजा आया। हमने पूछा क्या मजा आया तो उत्तर दिया कि आप होते तो आपको भी मजा आता। मजा जो हमें आया वह हमारी अनुभूति
~~~~~~~~

है और हम उसे भूल नहीं सकते पर शब्दों में आपसे व्यक्त नहीं कर सकते। अटलजी अभिमान हैं। अटलजी स्वाभिमान हैं। अटलजी सम्मान हैं। अटलजी अनुराग हैं। अटलजी सहज हैं। अटलजी आशीष हैं। अटलजी स्नेह हैं। अटलजी समुख हैं। अटलजी सत्यम् शिवम् और सुन्दरम् हैं। अटलजी साहित्य हैं। अटलजी कवि हैं। अटलजी प्रख्यात चिंतक हैं। उनकी दूरदृष्टि के सभी कायल हैं। वे मूल में विचारक हैं। वे गीतायण, सीतायण और रामायण के प्रतीक हैं। वे कल–कल बहती सरिता हैं। वे विंध्याचल के अटूट पहाड़ हैं। उनमें मां का ममत्व है तो उनमें पिता का पुण्य भी है।

'अटलजी' संसद के गौरव हैं तो वे गांव के ग्रामीणों की आत्मा की आवाज भी हैं। वे कुल देवता हैं। वे ग्राम देवता हैं। वे शीतल छायेदार वृक्ष हैं। वे मित्रों के मित्र हैं ही पर जो उन्हें अपना नहीं मानते उसे भी वे अपना लेते हैं। वे राजनीति की आस्था और निष्ठा हैं। वे राजनीति में 'विश्वास' हैं। वे राजनीति में मर्यादा के पालक हैं। वे शालीनता और विनम्रता के पुंज हैं। वे 'वरद्' पुंज हैं। वे शब्दों के साधक हैं और भारत मां के आराधक हैं। उनकी रग–रग में भक्ति और जनशक्ति है। वे 'आनंद' के प्रतीक हैं। वे अंधेरे के लिए प्रकाश हैं।

अटलजी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। वे जब प्रधानमंत्री बने तो संघ ने ही नहीं उन्होंने स्वयं ताकत से और स्नेह से कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। वे संकल्प के धनी हैं। जनता पार्टी बनी तो राष्ट्रहित में जनसंघ विसर्जित कर दिया और जब दोहरी सदस्यता का सवाल खड़ा किया तो साफ शब्दों में कहा कि जिस आंचल में बचपन बीता, उसे कैसे छोड़ सकते हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बद्ध है और सदैव रहेगा। आप चाहे तो विचार करें। हमारा तो विचार सदैव अडिग और अमर है। विचारधारा की यह प्रबलता आज की भारतीय राजनीति भोग रही है। आज राजनीतिज्ञों के जीवन में विचारधारा में आई लचरता अनेक प्रश्न खड़े करती है। अटलजी हर परीक्षा में खरे उतरे। वे 'सच' हैं। उन्होंने सदैव स्पष्टता रखी और अपनी बात कही, पर माना वही जो सामूहिक निर्णय हुआ। पत्रकार होने के नाते और खासकर ग्वालियर का होने के नाते और श्री अनूप मिश्रा के छात्र मित्र होने के नाते अटलजी से कार्यकर्ता के नाते तो परिचय है ही, पर उन पर हमारा स्वदेशीय अधिकार रहा। वे स्वदेश के संपादक रहे और हम स्वदेश में रहे। यह हमारे लिए गौरव की बात रही।

''अटलजी'' शब्द नहीं और केवल नाम नहीं है। 'वे' बहुत विषयों के शोधित ग्रंथ हैं। वे दर्शन है। वे शानदार ''डिप्लोमेट'' रहे। वे भारत को जानते थे और भारत के साथ–साथ भारत की चित्ति को भी जानते थे। यही कारण था कि जब वे प्रधानमंत्री बने तो गांव–गांव में खुशियां मनी। पहली बार भारत के बजट में लोगों ने गांव के दर्शन किए। भारत में नेता बहुत हैं और होंगे भी पर इस सच से कौन इंकार कर सकेगा कि अटलजी में भारत और भारत में अटलजी जैसा, लंबे समय की राजनैतिक पंक्ति में कोई खड़ा नहीं दिख रहा।

अक्सर अटलजी के बारे में आज लोग कहते सुने जाते हैं कि सरकार एक वोट से चली गई पर भारतीय संसद और भारतीय राजनीति की साख पर अटलजी ने आंच नहीं आने दी। प्रधानमंत्री की कुर्सी भारत की प्रतिष्ठा से बड़ी नहीं मानी। सवाल एक वोट का था, पर उन्होंने कहा कि खरीद–फरोख्त की कुर्सी पर बैठना लोकतंत्र की हत्या है। हमें लोकतंत्र में उन मानकों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे पुरखों ने स्थापित किए हैं। आज क्या स्थिति है? क्या ''वोट फॉर कैश'' पर बची कांग्रेस नीत यूपीए सरकार मुंह दिखाने लायक बची है? 'अटलजी' वे शख्स है, जिन्होंने स्वयं सदन में छोटी सी उम्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू से दो–दो हाथ किए थे।

'अटलजी' और 'लालजी' (लालकृष्ण आडवाणी) की जोड़ी बेमिसाल रही। विश्वास की ऐसी कड़ी भारतीय राजनीति का अनुपम उदाहरण है। 'अटलजी', देश चाहता है कि आप स्वस्थ्य हों। 'आप' के प्रति प्रत्येक देशवासी की शुभकामनाएं हैं। भारतीय राजनीति में विपक्ष में रहकर सत्तापक्ष मे अपने प्रति असीम साम्मान और सत्ता में रहकर विपक्षियों के मन में अनमोल स्थान बनाने की जो दैवीय शक्ति अटलजी में रही वह भारत सदैव याद करता है। वे भले ही अस्वस्थ हैं, पर उनके स्वस्थ होने की कामना करोड़ों लोग ईश्वर से हाथ जोड़कर कर रहे हैं। ■

अक्सर अटलजी के बारे में आज लोग कहते सुने जाते हैं कि सरकार एक वोट से चली गई पर भारतीय संसद और भारतीय राजनीति की साख पर अटलजी ने आंच नहीं आने दी। प्रधानमंत्री की कुर्सी भारत की प्रतिष्ठा से बड़ी नहीं मानी। सवाल एक वोट का था, पर उन्होंने कहा कि खरीद–फरोख्त की कुर्सी पर बैठना लोकतंत्र की हत्या है। हमें लोकतंत्र में उन मानकों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे पुरखों ने स्थापित किए हैं।

पलायन से झेला बेइंतिहा दर्द...

lit ; feJk

Vkज भी कोई यह कहने की स्थिति में नहीं है कि पलायन का सिलसिला कब रूकेगा? गांवों से लोगों ने शहरों की ओर रूख किया तो शहरों के बाशिंदों ने अच्छे अवसर की तलाश में विदेशों की राह पकड़ ली। हालांकि गांवों से शहरों में आने वालों की रफ्तार को शहरों से विदेशों की ओर जाने वालों की चाल कभी भी मात नहीं दे सकी। एक तरफ गांव वीरान होने लगे, दूसरी तरफ मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरू जैसे शहरों पर बोझ बढ़ने लगा। गांवों में गुजर–बसर करने वालों को शहर की रंगीनियां इतनी रास आई कि उन्होंने डेरा डाल लिया। ये डेरे झुग्गियों के आकार में शुरू होकर गंदी बस्तियों में तब्दील हो गए। अपनी जड़ों से उखड़ने का दर्द भले ही इन्हें नहीं सालता हो, मगर माटी की सुगंध से दूर होकर ये लोग धूल, धुएं और बनावटी रिश्तों की घुटनभरे माहौल की पीड़ा भोगने लगे।

अपनेपन से दूर झेल रहे बेगानापन

गांवों में जिस अपनेपन को उन्होंने जीया वह यहां सपना साबित हुआ। कठोर यथार्थ का सामना करने के बाद रिश्तों का मिजाज भी बदलने लगा। तमाम रिश्ते जो भावनाओं की डोर से बंधकर जिंदगी को मायने देते थे, धीरे–धीरे खोखले संबोधनों में बदलने लगे। यह बदलाव इतनी तेजी से हुआ कि व्यक्ति आत्मकेन्द्रित होता गया है। अकसर कहा जाता है कि दुनिया सिमट रही है। हालांकि यह संदर्भ सूचना क्रांति के बाद आए बदलाव से जोड़ा जाता है लेकिन गहराई से पड़ताल करें तो यकीन होने लगता है कि भले ही दुनिया 'ग्लोबल विलेज' बनी हो या न बनी हो, लेकिन व्यक्ति की दुनिया जरूर खुद के ईदगिर्द सिमट गई है। सूचना क्रांति ने भले ही दूरदराज में रहने वालों लोगों को जोड़ दिया हो लेकिन रिश्तों के रसायन में आए बदलाव होगा। व्यक्ति की दुनिया खुद तक सिमट गई है। न किसी से कोई रिश्ता, न किसी से कोई नाता। यदि है भी तो दिखावे की आड़ में औपचारिकता। जिन्हें लगता है कि पिता का आदेश मानकर भगवान राम का वन में चौदह साल बिताना मात्र किताबी ख्याल है तो

से दिलों के बीच दूरियां बढ़ी हैं।

एसएमएस बने परिवारों का संवाद

कभी पूरा गांव, मोहल्ला सुख–दुःख का हिस्सेदार होता था, आज पति–पत्नी, पुत्र–पिता और तमाम रिश्तों के बीच एसएमएस डोर का काम रहे हैं। एसएमएस की तरह संवाद का संक्षिप्तीकरण होता जा रहा है। दिक्कत यहां भी नहीं है। लिखी बात कही बात से अधिक असरकारक मानी जाती है, मगर जब शब्दों से भाव गायब हो गए हों तो रिश्तों में एहसास कहां से पैदा यकीन मानिए कि कल की पीढ़ी की बात तो दूर है मौजूदा पीढ़ी ही यकीन नहीं करती है कि अपने माता–पिता की खातिर किसी अन्य जगह जाकर नौकरी नहीं की।

'ब्रो' और 'सिस' का बोलबाला

अब तो रिश्तों के नाम भी बदल गए हैं। माता–पिता 'मॉम–डैड' हो गए हैं। भाई 'ब्रो' तो बहन 'सिस' बन गई है। इन बदलते नामों ने रिश्ते के अहसास को भी बदल दिया है। यह रिश्तों की कंगाली का दौर है इसलिए

भी है क्योंकि रिश्तों के अर्थ खो गए हैं। जो लोग मुंहबोले रिश्तों के अर्थ खो गए हैं। जो लोग मुंहबोले रिश्तों को पीढ़ियों तक सहेजते रहे हैं, आज जन्मजात रिश्तों का दायित्व उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। रिश्ते बोझ लगने लगे हैं और व्यक्ति चाहते न चाहते हुए कभी न कभी बोझा उतार ही देता है। यही वजह है कि शहर से गांव लौटने पर बड़े–बूढ़े, दोस्त–यार, पड़ोसी उलाहना देते नजर आते हैं कि वह बदल गया है क्योंकि यह बदलाव रहन–सहन या लिबास का न होकर व्यवहार का होता है, भावनाओं का होता है, भावनाओं के पीछे छिपी नीयत का होता है। स्वाभाविक सहजता की जगह स्वार्थपूर्ण चतुराई ले चुकी होती है। संबंध नफे–नुकसान की तुलना में तौले जाने लगते हैं और व्यक्ति इस्तेमाल की वस्तु बन जाता है। किसी समय गांव का एक व्यक्ति शहर में नौकरी पा लेता था, तो धीरे–धीरे पूरे गांव को अपने साथ जोड़ने की जुगत में लगा रहता था। गांव का कोई व्यक्ति शहर में किसी काम से आता था तो उसका डेरा शहर में बस चुके अपने गांववाले का घर होता था। गांव से व्यक्ति बेधड़क शहर में काम से आ जाता था क्योंकि उसे भरोसा था कि अगर कभी कुछ ऊंच–नीच हुई या कोई परेशानी हुई तो यहां अपना कोई है। अब तो लोगों को अपनी आस–औलाद पर ही यकीन नहीं रहा कि वह आड़े वक्त में काम आएगी या नहीं, ऐसे में गैरों से कौन उम्मीद करेगा। जो लोग किन्हीं कारणों से शहर से दूर थे या दूर रहे तो शहर उनके यहां खुद पहुंच गया। शहरी लटके–झटके, रहन–सहन, खान–पान की आड़ मे शहरी माहौल वहां प्रवेश कर गया और शहरी दांवपेच ग्रामीणों का हिस्सा बनते गए। पहले गांवों में छाछ बेची नहीं जाती थी। मगर अब तो गोबर तक (कंडों के रूप में) बिकने लगा है।

हुई खत्म गांव की मासूमियत

टीवी के आने के बाद गांव की मासूमियत और निर्मलता को शहरी संस्कृति लील गई। शहरी संस्कृति के बढ़ते दायरे ने गांवों का स्वरूप ही नहीं बदला बल्कि वहां के लोगों की 'लाइफस्टाइल' बदल दी। काली मिट्टी से नहाने वाले ग्रामीण अब महंगे साबुनों का उपयोग करते हैं टीवी देखकर नकली रिश्तों की आस लगाने लगे हैं।

कभी पूरा गांव, मोहल्ला सुख–दुःख का हिस्सेदार होता था, आज पति–पत्नी, पुत्र–पिता और तमाम रिश्तों के बीच एसएमएस डोर का काम रहे हैं। एसएमएस की तरह संवाद का संक्षिप्तीकरण होता जा रहा है। दिक्कत यहां भी नहीं है। लिखी बात कही बात से अधिक असरकारक मानी जाती है, मगर जब शब्दों से भाव गायब हो गए हों तो रिश्तों में एहसास कहां से पैदा होगा। व्यक्ति की दुनिया खुद तक सिमट गई है। न किसी से कोई रिश्ता, न किसी से कोई नाता। यदि है भी तो दिखावे की आड़ में औपचारिकता।

जीवन की असली खुशबू भूलकर बनावटी जीवन की ओर दौड़ने लगे हैं। खेतों में मेहनत कर जीवनयापन करना अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है, खेत बेचकर वे शहर में 'व्हाइट कॉलर जॉब्स' पाने के लिए वहां छोटा मकान खरीदने के लिए बेचैन हो चुके हैं। भौतिक सुखों की चाह बहुत बढ़ चुकी है और शहर की 'लाइफ स्टाइल्स' से प्रेरित होकर वे भी उसका हिस्सा बन रहे हैं।

शहरी जीवन का प्रहार

महानगरों में पहुंचे लोगों की आस्था अब पारंपरिक नहीं रही। वे दिखावे की संस्कृति में डूबकर रिश्तों को भूलने लगे हैं। वे सीमित जगह के कारण मित्रों, रिश्तेदारों को निश्चित समय के लिए बुलाते हैं या खुद घर कभी–कभार आ पाते हैं। शहरी जीवन की व्यस्तता और आर्थिक कुचक्रों में घिरकर वे रिश्तों का बोझ बिल्कुल नहीं उठाना चाहते। बड़ी विचित्र विडंबना है कि मुंबई से बाहर जाने वालों को कहा जाता है गांव या मुलुक जा रहे हो। न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस से आने वाले लोग मुंबई को मुलुक मानते हैं।

किसी समय गायों के झुंड जब शाम को वापस घर लौटते थे उस समय सुनहरी किरणों के बीच उड़ती धूल को देखकर कहा जाता था यह गोधूलि बेला है, लेकिन जब गांवों में ही गायों का टोटा पड़ गया हो तो कहां से नजर आएगी गोधूलि बेला। आज स्थिति यह है कि गांव न तो गांव रहे हैं और न ही शहर बन पाए हैं। अपना मूल स्वरूप खो चुके ये गांव आज ये शहर–गांव की अधकचना खिचड़ी बन गए हैं। गांधीजी ने विकेन्द्रीकरण पर इसलिए जोर दिया था। वे चाहते थे कि शहरों पर जनदबाव न बढ़े। वे कुटीर उद्योगों के जरिए जनसंख्या के बड़े हिस्से को जहां हो जैसे हो, विकास करो की नीति पर अमल करवाकर जीवन जीने की पद्धति सिखाना चाहते थे। औद्योगिकरण की आंधी सब लील गई है। अभी भी समय है कि हम फिर से सोचें और जीवन को लौटाएं ऐसे आंगन में जहां सुख हो, शांति हो, प्रेम हो और मिलकर रहने की चाह हो। तभी देश की गति भले ही विकास के पैमाने पर थोड़ी धीमी हो लेकिन जीवन के राजपथ पर प्रेम, संयम, सहजता के साथ सही मायनों में विकास करेंगे। ■

(साभार : दैनिक भास्कर)

कर्मयोगी कुशाभाऊ ठाकरे

çHkkr >k

d शाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ के जीवनभर प्रचारक रहे। मुझे उनके साथ काम करने का बहुत सौभाग्य मिला। मैं जिन अर्थों में 'स्वयंसेवक' की बात कर रहा हूं, वह अद्‌भुत है। 'कुशाभाऊ ठाकरे, बहुत बीमार थे। उन्हें देखने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक मा. सुदर्शनजी आए। हम वहीं खड़े थे। सुदर्शनजी ने जोर से कहा क्या, कुशाभाऊ कब तक ठीक हो रहे हो। इस पर ठाकरेजी ने कहा कि मैं तो देह त्यागने की अनुमति चाहता हूं। जीवनभर संघ का आदेश सर्वोपरि रहा। मुझे अब आपका आदेश चाहिए। मुझे शांति मिलेगी। मैं स्वयं 'एम्स' (अस्पताल) के उस कमरे में था। हम सभी भावविह्वल हो गए। सभी की आंखें भर आयीं। मेरे मन में उसी समय आया कि कैसे–कैसे लोग इस धरा पर आए। प्रतिबद्धता का ऐसा अनुपम अंगीकृत उदाहरण कहां देखने को मिलता है। स्वयं को संघ का सेवक बनकर निरंतर कार्य करने की प्रेरणा मुझे 'कुशाभाऊ' से सदैव मिलती रही। 'मिट्टी' से गणेश बनाने की क्षमता के वे धनी थे। हमने मध्यप्रदेश में कुशाभाऊ जैसे संगठन के शिल्पी के हाथों अनेक कार्यकर्ताओं को आते देखा और उन कार्यकर्ताओं की क्षमताओं का दल के लिए उपयोग करते देखा।

कुशाभाऊ 'कार्यकर्ताओं' के कार्यकर्ता थे। उनका संबंध परिवारों की पीढ़ियों से रहता था। वे वर्तमान और भविष्य दोनों के कंधों पर भार रखते थे। वे 'समर्पण' की जीती जागती मिसाल थे। अनवरत प्रवास उनके कार्य के नींव में थी। वे अक्सर कहा करते थे, ''कम खाना और गम खाना'' राजनीति में सदैव फायदेमंद होता है'। वे नैतिकता के पुजारी थे। कुशाभाऊ के नैतिक बंधन में छोटे से बड़े सभी नेता बंधे हुए थे। वे राजनीति में साधक थे। उन्होंने जनसंघ के 'दीए' को अखंड प्रज्जवलित रखने के लिए अपना खून–पसीना एक किया। वे कभी मुरझाए नहीं। वे बालबोध से ओत–प्रोत थे और सबको सुलभ उपलब्ध थे। कार्यालय ही उनका घर था। जहां कार्यालय नहीं वहां कार्यकर्ता का घर। वे कभी सर्किट हाऊस या अन्य स्थानों पर नहीं रुके। वे सुविधाओं के मोहताज नहीं थे। उन्होंने कभी अपने साथ ऐसा कार्यकर्ता नहीं रखा, जिससे संगठन का नुकसान हो। एक बार की बात है। वी. सतीश जी, जो वर्तमान में भाजपा के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री है, को उनका संघ की ओर से सहयोगी के रूप में दिया गया। कुछ ही महीनों में पता चला कि वी. सतीश नार्थ–ईस्ट के संगठन मंत्री होकर चले गए। हमने जब कुशाभाऊ से पूछा कि अब आपके सहयोगी कौन है? उन्होंने कहा कि वह संघ का प्रचारक था और काफी पढ़ा लिखा था। उसका उपयोग संगठन के कार्यों में अधिक था, इसलिए मैंने स्वयं संघ से चर्चा कर उसे संगठन कार्य सौंप दिया। वहीं मेरा काम तो रवीन्द्र, जो अभी केन्द्रीय

कुशाभाऊ 'कार्यकर्ताओं'' के कार्यकर्ता थे। उनका संबंध परिवारों की पीढ़ियों से रहता था। वे वर्तमान और भविष्य दोनों के कंधों पर भार रखते थे। वे 'समर्पण' की जीती जागती मिसाल थे। अनवरत प्रवास उनके कार्य के नींव में थी। वे अक्सर कहा करते थे, ''कम खाना और गम खाना'' राजनीति में सदैव फायदेमंद होता है'। वे नैतिकता के पुजारी थे। कुशाभाऊ के नैतिक बंधन में छोटे से बड़े सभी नेता बंधे हुए थे। वे राजनीति में साधक थे। उन्होंने जनसंघ के 'दीए' को अखंड प्रज्जवलित रखने के लिए अपना खून–पसीना एक किया।

कार्यालय में है और तुम्हारा राजेन्द्र सिंह, जो वर्तमान में भाजपा मध्यप्रदेश के सह–कार्यालय मंत्री हैं, से चल जाएगा। स्व. कुशाभाऊ ठाकरे स्वयं में एक संगठन थे। उनके जीवन चरित्र से तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे के परिजनों से कहा कि मैंने पं. दीनदयाल उपाध्याय को देखा नहीं, पर जितना पढ़ा था, उसको पढ़ने के बाद वो सभी बातें मैं स्वयं कुशाभाऊ ठाकरे में देख रहा हूं। वे हमारे आज के दीनदयाल उपाध्याय हैं। इतना कहते हुए वेंकैयाजी रोने लगे।

पूर्व में जनसंघ, अब भाजपा, सदैव वही परिवार भाव, न कि परिवारवाद से। जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यात्रा में परिवार भाव के कारण ही हमारा सदैव विस्तार हुआ। ठाकरेजी मानवीय संस्कारों से जुड़ी संवेदनाओं के पुजारी थे।

एक बार एक दुर्घटना में मुरैना के तत्कालीन सांसद छविराम अर्गल की मृत्यु हो गई। ठाकरे जी मुरैना स्थित उनके घर गए। हम लोग साथ में थे। उन्होंने घर की परिस्थिति देखी तो कोई परिवार में बड़ा नहीं था। ठाकरेजी ने कहा कि हमारा छविराम सरकारी नौकरी में था, शिक्षक था। मैंने इसकी नौकरी छुड़वाई थी। वह हम सबको छोड़कर चला गया। उनके ध्यान में यह बात बनी हुई थी कि छविरामजी के घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं था। सभी छोटे–छोटे थे। सन् 1990 में भाजपा की सरकार आयी। मुझे स्वदेश में ठाकरेजी का फोन आया। उन्होंने कहा कि तुम छविरामजी के यहां जाओ और बता दो कि उनके छोटे–बेटे को हमने बुलाया है। हमने सूचना थी। छविरामजी का छोटा बेटा भोपाल पहुंचा। ठाकरे जी ने वहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री पटवाजी के सामने सारी बातें रखी। पटवाजी ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती प्रारम्भ हो रही हैं, उसमें भर्ती हो जाएगी। ठाकरेजी ने पूरा ध्यान रखा और जब तक उसकी नौकरी नहीं लगी वे इस बात के पीछे लगे रहे। अंततः वह शिक्षक बन गया। ठाकरेजी ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा कि ''कच्चा परिवार था, अतः यह आवश्यक था।'' ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, जो लिखे जा सकते हैं।

'स्व. कुशाभाऊ ठाकरे' जैसे व्यक्तित्व की आज महती आवश्यकता है। कोई भी संगठन या संस्था, समाज या राष्ट्र समर्पण और आध्यात्मिक साधना से ही चलता है। नैतिक बंधन से मुक्त समाज या संगठन कभी लंबे समय तक पटरी पर नहीं चल सकता। भारतीय राजनीति में सदैव समर्पण की पूजा हुई है। यही कारण है कि ऐसे नैतिक लोगों की समाज और संगठन में सदैव आवश्यकता रही है।

स्व. कुशाभाऊ ठाकरे राजनीति में चालाकी या चार्तुयता नहीं करते थे। वे आचरण से लोगों की मानसिकता बदलने में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने आचरण–व्यवहार से ही दल और दल के बाहर के लोगों के मन में स्थान बनाया। उन पर लिखी 'शिल्पी' पुस्तक उनके जीवन को स्वयं दर्शाती है।

स्व. कुशाभाऊ ठाकरे नेपथ्य में रहते थे। वे जब तक अध्यक्ष नहीं बने तब तक वे खुद अग्रणी पंक्ति में नहीं रहते थे। वे अक्सर कहते थे, भारत की राजनीति अमीरी से ओत–प्रोत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा राजनीति में अनावश्यक खर्च से भ्रष्टाचार पनपता है। वे आवश्यक खर्च के हिमायती थे। उन्होंने कहा कि भाजपा पर देश का दायित्व हैं और दलों पर नहीं क्योंकि हम तो पैदा ही राष्ट्रवाद के लिए हुए। भाजपा देश में एकमात्र राजनैतिक दल है, जो कांग्रेस की कोख से पैदा नहीं हुआ, अन्यथा तो सभी दल कहीं न कहीं कांग्रेस के करीब ही रहे हैं।

उनका आदिवासियों के प्रति जो लगाव था, वो देखते ही बनता था। जब वे अस्पताल में थे, तो उनकी सेवा में स्वयं श्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी श्रीमती साधना सिंह लगी हुई थी। वे शिवराज सिंह जी से सदैव एक ही बात कहते रहते थे कि मध्यप्रदेश और देश में आदिवासियों की चिंता कौन करेगा? तुम सभी लोग आदिवासियों की चिंता करते रहना। वे सच में समाज शिल्पी थे। उन्होंने राजनीति की रपटीली राहों पर कमल के फूल खिलाने का जो व्रत लिया था, उसका वे अंतिम सांस तक पालन करते रहे।

'ठाकरेजी' की सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम सभी राजनीति में नैतिकता और प्रामाणिकता से कार्य करते रहें। प्रतिबद्धता भूलें नहीं। हम सत्ता आराध्य दल नहीं बल्कि समाज आराध्य दल हैं। हमारे सामने देश पहले, दल बाद में और उसके बाद अपने बारे में विचार करना अच्छा माना जाता है। काश! ये वाक्य हम सभी के जीवन में चरितार्थ होने लगे। ■

'ठाकरेजी' की सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम सभी राजनीति में नैतिकता और प्रामाणिकता से कार्य करते रहें। प्रतिबद्धता भूलें नहीं। हम सत्ता आराध्य दल नहीं बल्कि समाज आराध्य दल हैं। हमारे सामने देश पहले, दल बाद में और उसके बाद अपने बारे में विचार करना अच्छा माना जाता है। काश! ये वाक्य हम सभी के जीवन में चरितार्थ होने लगे।

राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा तथा सुशासन हमारा मिशन है : गडकरी

gekj: loknnkrk }kjk

Hkkजपा के सुशासन प्रकोष्ठ ने 1 दिसम्बर 2011 को दिल्ली में इण्डिया इंटरनेशनल सेन्टर में एक समारोह में छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनूठे प्रबंधन पर "The difference that we made-1" शीर्षक से एक मोनोग्राफ जारी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह, महासचिव (संगठन) श्री रामलाल, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महासचिव श्री जे.पी. नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार श्री विनय सहस्रबुद्धे ने समारोह में भाग लिया।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि देश के सर्वाधिक महत्व का विषय सुशासन है। हमारा मानना है कि राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है और सुशासन हमारा मिशन है। हम 'अन्त्योदय' को भी दलितों की हालत में परिवर्तन का माध्यम समझते हैं। उन्होंने कहा कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती निर्धनता–उन्मूलन है। इसका कारण कुशासन है। हमारे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और गरीबी एक कलंक है।

श्री गडकरी ने आगे कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो हमारी जीडीपी तथा कृषि विकास बढ़कर क्रमशः 12 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। श्री गडकरी का यह भी कहना था कि सुशासन प्रकोष्ठ का यह दायित्व है कि वह कोई भी या किसी भी सरकार के लिए गए अच्छे कार्यों को सामने लाए ताकि दूसरे भी उन कार्यों के लिए प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि भाजपा का मानना है कि कहीं भी किए गए किसी भी अच्छे कार्य को प्रेरणास्रोत बनना चाहिए ताकि प्रत्येक भारतीय को प्रतिदिन–पूरा भोजन मिल सके, प्रत्येक नवजात शिशु जी सके और शिक्षा प्राप्त कर सके तथा अन्ततः वह भारत को एक खुशहाल जीवन रहने का स्थान बना सके। इस अवसर पर गडकरी ने घोषणा की कि श्री अटल जी के जन्मदिवस को 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। इस समारोह में श्री रमन सिंह ने भी अपने भाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भ्रष्टाचार और निर्धनता उन्मूलन की दिशा में उनकी सरकार ने कौन–कौन से कदम उठाए हैं? प्रकोष्ठ के सह–संयोजक श्री जगदीश मुखी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जिसने सुशासन प्रकोष्ठ के स्थापना की है। पूर्व राज्यपाल एवं आईआईपीए के अध्यक्ष श्री टीएन चतुर्वेदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों में भाजपा नेता डॉ. हर्षवर्धन भी उपस्थित थे।■

मध्यप्रदेश भाजपा की अभिनव पहल

'बिटिया बचाओ अभियान' का शुभारंभ

Hkkरतीय जनता पार्टी 'सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं अपितु समाज परिवर्तन' के ध्येय को लेकर कार्य करती है, इस दिशा में पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। अमूमन यही देखने को मिलता है कि राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य होते हैं – विरोध–प्रदर्शन, रैली, घेराव, सम्मेलन आदि आयोजित करना, जबकि रचनात्मक या विकास कार्य शासन के जिम्मे छोड़ दिए जाते हैं। वास्तव में समाज सशक्तिकरण के कार्य को सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए बल्कि समाज के सभी घटकों को इस महान कार्य के लिए आगे आना चाहिए।

लिंगानुपात में आ रही कमी चिंता का विषय है। भारतीय संस्कृति में स्त्री के देवी स्वरुप को हम पूजते हैं, फिर भी दुर्भाग्य से बेटियों की भ्रूण हत्या की जा रही है। इस संवेदनशील और गंभीर मसले पर भाजपा की मध्यप्रदेश सरकार ने 'बिटिया बचाओ अभियान' चलाया। भाजपा संगठन ने भी इस मुद्दे पर जन–जागरण की दृष्टि से सघन अभियान चलाया। गत 5 अक्टूबर को नवरात्रि की नवमीं के दिन इंदौर में इतिहास रचा गया। इस दिन भाजपा, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रभात झा एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 'बिटिया बचाओ अभियान' का शुभारंभ किया।

इस अनूठे अभियान के लिए अनूठी पहल की गई। इस कार्यक्रम के निमित्त आम तौर पर प्रचलित आमंत्रण–पत्र की जगह भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए अक्षत–रोली से युक्त आमंत्रण–पत्र तैयार किया गया था। वहीं इस दिन एक लाख बालिकाओं के पैर पूजे गए। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास से लेकर मंडल स्तर तक इस प्रकिया को संपन्न किया गया। मध्य प्रदेश भाजपाध्यक्ष श्री प्रभात झा ने 'बिटिया बचाओ अभियान' की सफलता सुनिश्चित करने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्ग का आह्वान किया, यह भी एक उल्लेखनीय पहल है।

श्री प्रभात झा का कहना है कि राजनीति सिर्फ वोट के लिए नहीं होती है। सामाजिक संतुलन, समाज का अलंकरण, समाज की मर्यादा, समाज की ऋचाएं, समाज का सम्मान, समाज का अरुणोदय करना भी राजनीतिक दल और सरकार का दायित्व होता है।

भाजपा ने तय किया है कि पार्टी की आधारस्तंभ रहीं स्व. राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जन्मदिन को 'बिटिया बचाओ' दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ■

समरस भारत बनाने का संकल्प लें कार्यकर्ता : नितिन गडकरी

loknnkrk }kjk

Hkk रतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा 6 दिसम्बर, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित 55 वां बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की परिनिर्वाण पुष्पांजलि कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान भारतीय समाज के विभिन्न अंगों में सामाजिक समरसता लाने के लिए प्रेरणा दी थी और उन्होंने अपने योगदान से भारतीय समाज के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के उत्थान में अतुलनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बाबा साहब के पदचिह्नों पर चल कर देश का निर्माण करना होगा जिसमें बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा सबसे बडी भूमिका निभा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण और समाज में गैर बराबरी खत्म करने के लिए जो कुछ किया, उस ऋण को हम चुका नहीं सकते। हम उनके मिशन को आगे बढायें, यही उनको सही श्रद्धांजलि है।

इस मौके पर भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, राष्ट्रीय मोर्चा/प्रकोष्ठ समन्वयक श्री महेन्द्र पाण्डेय, राष्ट्रीय महामंत्री श्री थावर चन्द गहलोत, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रामनाथ कोविन्द, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुष्यन्त कुमार गौतम दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता, भाजपा मुख्यालय प्रभारी श्री ओम प्रकाश कोहली, अनुसूचति जाति मोर्चा के कोषाध्यक्ष श्री मोहन दायमा, एवं श्री कृष्ण लाल ढिलोड, डा0 अनिता आर्य (पूर्व सांसद), शान्त प्रकाश जी, स्टेंडिग कमेटी के चेयरमैन श्री योगेन्द्र चन्दोलिया जी ने पुष्पांजलि अर्पित की।

इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, श्री थावर चन्द गहलोत, ने कहा कि बाबा साहेब ने हमारे समाज के उत्थान के लिए और समाज से छुआछूत मिटाने के लिए समाज के विभिन्न अंगों को एक साथ मिलकर चलने का संकल्प दिया। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हम उसी पथ पर आगे बढने का संकल्प लें। श्री दुष्यन्त कुमार गौतम राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, भाजपा ने इस

मौके पर बाबा साहब को श्रद्धाजंलि देते हुए कहा कि बाबा साहब किसी एक समाज के नेता नहीं थे बल्कि सम्पूर्ण समाज के नेता थे।

बाबा साहब ने संविधान की रचना करते वक्त एक समतामूलक समाज की कल्पना की थी और दलित समाज को आरक्षण दिला कर मुख्यधारा से जोड़ा। पूर्व सांसद श्री रामनाथ कोविन्द ने कहा कि भारतीय समाज से गैर बराबरी मिटाने में बाबा साहब का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है उन्होंने अपने अथक प्रयासों से संसद के बाहर और अन्दर कई मोर्चों पर संघर्ष किया। अनुसूचित समाज के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को अपना प्रेरणास्रोत्र मानकर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि बाबा साहब का तिरस्कार कांग्रेस हमेशा से करती आ रही है जबकि बाबा साहब का योगदान समाज के उत्थान में सबसे ऊपर रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके इस योगदान के लिए नमन करती है।

मा0 रामलाल जी ने कहा कि हमें बाबा साहब के पदचिह्नों पर चलने की आवश्यकता है और उनके बताये हुए 'शिक्षित बनो, संगठित रहो, ओर संघर्ष करो' के विचारों को अपनाने की जरूरत है। प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष श्री कृष्ण लाल ढिलोड ने मंच का संचालन करते हुए कहा कि बाबा साहब का योगदान हमारे समाज के पिछडे लोगों को ऊपर उठाने में सर्वोपरि रहा है जिसको हम 64 सालों से आरक्षण के माध्यम से उनके द्वारा हम समाज में बराबरी के हक को प्राप्त कर रहे हैं। बाबा साहब के इस 55 वें परिनिर्वाण दिवस पर हजारों की संख्या में आकर कार्यकर्ताओं ने उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। ■

उपचुनावों में राजग की जीत

l:oknnkrk }kjk

पनावी राजनीति की ऊंच–नीच के खेल में भाजपा–नीत राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन (राजग) अपनी ऊंच बराबर बनाये बैठा है। देश के सात राज्यों में हुये आठ विधान सभा व एक लोक सभा उपचुनाव में राजग ने चार, कांग्रेस–नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (संप्रग) ने मात्र दो स्थान प्राप्त किये हैं जो कांग्रेस के हिस्से गये हैं। मात्र एक लोक सभा उपचुनाव में कांग्रेस सहयोगी तृमूल कांग्रेस ने पश्चिमी बंगाल में अपनी स्थिति बनाई रखी। यह सीट मुख्य मन्त्री बनने व विधान सभा सीट जीत जाने के बाद सुश्री ममता बैनर्जी के लोक सभा से त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुई थी।

हिमाचल में कांग्रेस ने प्रतिष्ठा की एक सीट गंवाई और एक जीती। हरियाणा में कांग्रेस को एक सीट का लाभ अवश्य हुआ जो उसने श्री ओम प्रकाश चौटाला के राष्ट्रीय लोक दल से जीती। दूसरी सीट तो भाजपा–हरियाणा जनहित कांग्रेस की संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती रेणुका बिशनोई ने जीती।

अन्य प्रदेशों में कांग्रेस के हाथ कुछ न आया। बिहार की लौकहा सीट पर राजग के जनता दल (यू) प्रत्याशी श्री सतीश साह ने लालू प्रसाद के राजद को हराया। यहां कांग्रेस चौथे स्थान पर रही।

झारखण्ड में माण्डू विधान सभा उपचुनाव में राजग सहयोगी झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी श्री जयप्रकाश भाई पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी को पछाड़ा।

कर्नाटक में भाजपा को अवश्य हानि हुई जहां उसके हाथ से एक सीट निकल गई।

ओडीशा के उमरकोट विधान सभा उपचुनाव में बीजू जनता दल ने अपनी सीट बरकरार रखी। यहा भाजपा प्रत्याशी दूसरे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही।

हिमाचल में इतिहास

हिमाचल के चुनावी दंगल तो बराबरी पर छूटा। भाजपा व कांग्रेस दोनों ने ही एक–दूसरे से एक–एक सीट छीन ली। पर प्रतिष्ठा की बाज़ी मार गई भाजपा। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में 2007 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस के अब तक के अभेद्य किलों पर कब्ज़ा करने का सिलसिला शुरू हुआ था। तब भाजपा ने पहला दुर्ग गिराया जुब्बल–कोटखाई का जहां से कांग्रेस के पूर्व मुख्य मन्त्री ठाकुर रामलाल इतने सशक्त थे कि एक बार तो उन्होंने पदासीन मुख्य मन्त्री वीरभद्र सिंह को ही हरा दिया था। इस श्रृंखला को इस बार पूरा कर दिया जब भाजपा ने रेणुका विधान सभा चुनावक्षेत्र पर 3ए526 मतों की सम्मानजनक बढ़त से विजय प्राप्त कर ली। यह हिमाचल के प्रथम मुख्य मन्त्री और कांग्रेस दिग्गज यश्वन्त सिंह परमार का गृह क्षेत्र रहा है।

इस से पूर्व 2009 के उपचुनाव में भाजपा ने प्रदेश के पांच बार रहे मुख्य मन्त्री श्री वीरभद्र सिंह के चुनावक्षेत्र रोहडू पर कब्ज़ा जमा लिया था।

यह प्रथम अवसर है जब कांग्रेस के तीनों पूर्व मुख्य मन्त्रियों के चुनाव क्षेत्रों पर भाजपा ने 1952 के प्रथम चुनाव के बाद पहली बार विजय प्राप्त की।■

महंगाई, भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ भाजपा का संघर्ष जारी रहेगा : नितिन गडकरी

गत 4 दिसम्बर को नैनीताल में हुई राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक में संगठन विस्तार एवं पांच राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनावों की रणनीति तय की गई। बैठक में तय किया गया कि कालाधन, महंगाई व भ्रष्टाचार ही पार्टी का मुख्य चुनावी एजेंडा रहेगा। उत्तर प्रदेश में पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी।

नैनीताल क्लब में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार ने पत्रकारों से कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा व मणिपुर में होने वाले विधान सभा चुनाव की पार्टी ने रणनीति तय कर ली है। आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्मदिवस को देश भर में 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया है। आम आदमी को सुशासन का महत्व बताने के लिए नौ दिसंबर को भाजपा शासित प्रदेशों के मंत्रिमंडल की बैठक दिल्ली में होगी। इसके अलावा अन्य राज्यों में जहां भी नगर निकायों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक भाजपा काबिज है, वहां पर सुशासन की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बसपा से नाखुश है, सपा से नाराज है और केन्द्र में कांग्रेस सरकार के कुशासन से त्रस्त है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर केंद्र सरकार को रोलबैक करने के लिए भाजपा आवाज उठा चुकी है। इसके लिए संसद में संघर्ष जारी रहेगा।

राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक से पूर्व मीडिया से मुखातिब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार व कालेधन के खिलाफ शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी की जनचेतना यात्रा से आम जनमानस में पार्टी की साख बढ़ी है। उन्होंने उत्तराखंड में सशक्त लोकायुक्त विधेयक व सिटीजन चार्टर लागू करने के लिए मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी की प्रशंसा की।

बैठक के बाद स्थानीय मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री नितिन गडकरी ने 2जी, राष्ट्रमंडल खेल, गरीबी, बेरोजगारी, एफडीआइ के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार में कुशल नेतृत्व, विश्वसनीयता, साख, इच्छाशक्ति का पूरी तरह अभाव है। प्रधानमंत्री को उन्होंने गद्दी छोड़कर अमृतसर स्वर्ण मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करने की सलाह दी। गरीबी को लेकर केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे, किसानों के आत्महत्या के मामलों, पेट्रोल कीमतों में आए दिन बढ़ोतरी पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया।

एफडीआइ के मुद्दे पर केंद्र पर हमला जारी रखते श्री गडकरी ने कहा स्वदेशी का विचार देने वाली महात्मा गांधी की कांग्रेस सोनिया के नेतृत्व में विदेशी हो गई है। अल्पसंख्यकों के विषय में श्री गडकरी ने कहा देश की 36 प्रतिशत आबादी वाले राज्यों में भाजपा सत्ता में है और भाजपा शासित राज्यों में सबको विकास का समान अवसर दिया जा रहा है। जनसभा को पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री सर्वश्री भगत सिंह कोश्यारी व डा.रमेश पोखरियाल निशंक ने भी संबोधित किया।■

लखनऊ से दिल्ली तक की पदयात्रा

भाजपा मानवाधिकार प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित 'संकल्प अभियान'

देश के संविधान द्वारा गारंटीकृत मानवाधिकार उत्तर प्रदेश में सबसे निम्न स्थान पर पहुंचा हुआ है। यह देखकर बड़ी शर्म महसूस होती है कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ही वह स्थान है, जहां से सर्वाधिक मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रिकार्ड के अनुसार बलात्कार, हत्याएं, लूट–पाट और अपहरण जैसे अपराध इस राज्य के प्रशासन और कुशासन के कारण एक सामान्य सी बात होकर रह गई हैं। भाजपा मानवाधिकार प्रकोष्ठ ने उत्तर प्रदेश में 27 नवम्बर 2011 से 'संकल्प अभियान' के रूप में एक पदयात्रा का आयोजन किया।

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव सुश्री किरण माहेश्वरी ने प्रकोष्ठ के संयोजक श्री सुधीर

अग्रवाल के नेतृत्व में पदयात्रा को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया।

मानवाधिकार प्रकोष्ठ ने पदयात्रा के दौरान लोगों के साथ विचार विमर्श करने, सभाएं आयोजित करने तथा गांवों, कस्बों एवं शहरों में सभा–बैठकें करके राज्य में मानवाधिकार उल्लंघन सम्बन्धी जागृति फैलाने की संकल्प की है।

27 नवम्बर 2011 से शुरू की गई 'संकल्प अभियान' अनेक गांवों, कस्बों और शहरों से गुजरती हुई 15 दिसम्बर 2011 को दिल्ली पहुंचने की आशा है। ■

भाजपा निवेशक प्रकोष्ठ का विरोध मार्च

रुपए की कीमत में गिरावट पर भाजपा की गहन चिंता

20 नवम्बर 2011 को जन्तर–मन्तर, नई दिल्ली में भाजपा निवेशक प्रकोष्ठ ने हजारों कार्यकर्ताओं ने इतिहास में सबसे कमजोर पड़ते जा रहे रुपए की कीमत के विरोध में मार्च किया। उन्होंने

अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन और निरंतर गिरती जा रही रूपए की कीमत पर गहन चिंता प्रगट की जिसके कारण यूरिया (उर्वरक), औषध–तेल, पेट्रोलियम पदार्थ और पूंजीगत माल आदि के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे आम आदमी बुरी तरह प्रभावित होगा जो पहले ही कष्ट भोग रहा है। रुपए की कीमत गिरने के कारण पिछले तीन महीनों में 20 से 22 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है क्योंकि जो रुपया 11 अगस्त को 44 रूपए का था, वह अब 52 रुपए प्रति डालर तक पहुंच गया है। सरकार के कुप्रबंधन से उत्पन्न आयात बिल का बोझ आम आदमी को ही तो सहना पड़ेगा।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश जावडेकर ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार की पूरी अर्थव्यवस्था की विफलता की स्थिति पैदा करने के लिए नीति–निर्माताओं को दण्डित किया जाना चाहिए।

आर्थिक प्रबंधन को अमरीका और पश्चिमी देशों के स्तर पर नहीं चलाया जा सकता है और हमें भारतीय परिवेश के संदर्भ में ही अपनी आर्थिक नीतियां बनानी चाहिए। भाजपा निवेशक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरूण सिंह ने रुपए की गिरती कीमतों पर गहरी चिंता प्रगट की और कहा कि यह भी चिंता का विषय रहा है कि नीति–निर्माता तथा सरकार एक–दूसरे के बयानों का खण्डन करके आम आदमी को भ्रमित कर रही है।

अधिकांश कम्पनियों को बढ़ती आयात लागत और 14 गुणा बढ़ती ब्याज दर के कारण नुकसान उठाना होगा। लाखों निवेशकों को स्टाक एक्सचेंज पर विश्वास नहीं रह गया और वे गलत नीतियों के कारण भ्रमित, चिंहित और कुण्ठित हो गए हैं। श्री अशोक गोयल, सह–संयोजक, श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राष्ट्रीय सह–संयोजक, श्री रोशन कंसल, दिल्ली स्टेट सह संयोजक तथा हजारों निवेशकों ने विरोध मार्च में भाग लिया। ■